

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 09 दिसंबर 2020 वर्ष-3, अंक-310 पृष्ठ-08, मूल्य-01 रुपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पुरानी गाड़ियों में हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट लगाने की जरूरत नहीं, आदेश स्थगित

लखनऊ। दो वार पहिया समेत सभी प्रकार के गाड़ी मालिकों के लिए राहत की खबर है। यूपी में एक अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट लगवाना अब जरूरी नहीं होगा। क्योंकि परिवहन विभाग ने एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ऐसे में 22 अक्टूबर 2020 को परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देश को वापस ले लिया गया है। दरअसल, पुराने वाहनों में हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता ने गाड़ी मालिकों को परेशान कर दिया था। कहीं ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत सामने आ रही थी तो कहीं नंबर प्लेट के बदले मनमानी पैसा लिया जा रहा था। गाड़ी मालिकों की इस समस्या को देखते हुए परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त एके पांडेय ने कहा कि अब पुराने वाहनों में एचएसआरपी लगवाना जरूरी नहीं है। इसके लिए बाद में पुनः आदेश दिया जाएगा।

परिवहन विभाग खुद बनाएगा वेबसाइट-हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग को आसान बनाने के लिए परिवहन विभाग खुद वेबसाइट बनाएगा। इसके लिए विभाग सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैनुफैक्चर्स से मिलकर पोर्टल तैयार करेगा। इसके बाद ही एचएसआरपी लगवाने की अनिवार्यता को तारीख तक की जाएगी।

इन सभी कामों पर लगी रोक हटी-एचएसआरपी की अनिवार्यता खत्म होने पर आरटीओ में वाहन संबंधी कार्यों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन, स्वामित्व अंतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइड्रोथैकेशन पृष्ठकन, हाइड्रोथैकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, नेशनल परमिट आदि के काम अब बिना एचएसआरपी रसीद के हो सकेंगे।

किसानों के समर्थन में सोनिया गांधी नहीं मनाएंगी जन्मदिन

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों द्वारा 'भारत बंद' बुलाया गया है। यह बंद देशभर में सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। भारत बंद के निर्णय को कांग्रेस समेत कई अन्य पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। अब इसी सिलसिले में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस साल अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। सोनिया गांधी हर साल अपना जन्मदिन 9 दिसंबर को मनाती हैं, लेकिन इसबार वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। उन्होंने यह फैसला देशभर में चल रहे कृषि आंदोलन और कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए लिया है।



सोनिया गांधी हर साल अपना जन्मदिन 9 दिसंबर को मनाती हैं, लेकिन इसबार वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। उन्होंने यह फैसला देशभर में चल रहे कृषि आंदोलन और कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए लिया है।

राजद समेत 18 से ज्यादा विपक्षी दलों ने भारत बंद को समर्थन दिया है। उनके अलावा 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने नैतिक समर्थन दिया है। साथ ही, रेलकर्मियों के संगठन बैक यूनियन, व्यापारियों की कई संस्थाएं दिल्ली-एनसीआर में मंडी समितियां, वकीलों के

कुछ संगठन, खाप पंचायतों ने समर्थन दिया है।

बता दें, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजपुर बॉर्डर समेत कई बॉर्डर पिछले कुछ दिनों से बंद हैं। अब इस आंदोलन का असर न सिर्फ यात्रियों पर पड़ रहा है, बल्कि फल-सब्जी के दाम भी बढ़ने लगे हैं।

कोविड-19 भी है एक वजह-कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए भी सोनिया गांधी अपना जन्मदिन नहीं मना रही हैं। भारत में सोमवार को कोरोनावायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 96 लाख 77 हजार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में सोमवार को पिछले 24 घंटे में 32,981 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 96,77,203 हो गई है। इस दौरान 391 लोगों की मौत हो गई है।

कृषि कानूनों के समर्थन में उतरा एक किसान संगठन कृषि मंत्री से की कानून रद्द न करने की अपील

नई दिल्ली। देशभर में पंजाब, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आंदोलन तेज करते हुए किसानों ने आज यानी मंगलवार को 'भारत बंद' बुलाया है। मगर एक किसान संगठन ऐसा भी है जो इस वक्त सरकार के साथ है। सोमवार को हरियाणा किसानों के एक संगठन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कृषि मंत्री से कानून को रद्द न करने की अपील की है। 'हर किसान' नाम के संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले किसानों ने कृषि कानूनों के सिलसिले में कृषि मंत्री से मुलाकात की है। 116 किसान-स्वामित्व वाले कृषि उद्यमों वाले इस संगठन ने मंत्री से अपील की है कि वह कृषि कानूनों को रद्द न करें। पदाधिका मन्मोहन कंवल सिंह चव्हाण की अगुवाई में गए इस किसान संगठन ने कहा कि वह संशोधन का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार बेशक संशोधन कर लेकिन वह चाहते हैं कि कानून लागू हो। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि एमएसपी जारी रहे, हम यह भी चाहते हैं कि मंडी व्यवस्था बनी रहे लेकिन हम भी अधिक विपणन विकल्प चाहते हैं, जो इन नए कानूनों की मदद से बनाए जाएंगे। नए कानूनों से कृषकों और खेती-बाड़ी को लाभ होगा। उन्होंने यह भी कहा कि

सरकार ऐसे आंदोलनों से खुद निपटेगी। विरोध कर रहे किसानों को भूमित किया गया है इन किसानों के साथ भारतीय किसान यूनियन (अंतर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतर सिंह संघु भी शामिल रहे। संघु ने कहा कि हम नये कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं, यदि एमएसपी के बारे में लिखित में दे दिया जाता है तो सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि विरोध कर रहे किसानों को राजनीतिक लाभ के लिये प्रेरित किया गया है। प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, ऐसे चलेगा आंदोलन बेगार? इससे तो सरकार निपटेगी। आप लोग इन कानूनों का समर्थन करने के लिये पहुंचे हैं, आपका हृदय से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। बता दें, सरकार और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। विरोध कर रहे किसान इन कानूनों को निरस्त किये जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं पर सरकार का कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इनसे किसानों को अपनी उपज देश में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।

सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी- हेट स्पीच को अपराध बनाने की जरूरत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री स्पीच की आड़ में हेट स्पीच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच क्या है और किस हेट स्पीच कहा जाए। ये तय करने के मापदंड बनाए जाने होंगे। जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने सोमवार को दिए फैसले में कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुलवाद के लिए प्रतिबद्ध है, उसमें हेट स्पीच से बराबरी के अधिकारों का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीच और हेट स्पीच के बीच में अंतर करना होगा। हेट स्पीच को आपराधिक बनाने का उद्देश्य व्यक्ति के सम्मान की सुरक्षा करने के साथ विभिन्न समूहों की बराबरी के अधिकारों को संरक्षित करना है। कोर्ट ने कहा हेट स्पीच से समाज में कटुता बढ़ती है, जिसे रोकने की जरूरत है। कोर्ट ने ये टिप्पणियां एक टीवी एंकर के खिलाफ एफआईआर समाप्त करने से इंकार करते हुए की। उस पर अजमेर दरगाह के खिलाफ टिप्पणियां करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आम लोगों के बीच अपनी 'पहुंच, प्रभाव' आदि को देखते हुए प्रभावशाली लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों का अपना कर्तव्य भी है।

न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नफरत वाले भाषणों के विभिन्न पहलुओं पर गौर किया। न्यायालय ने कहा कि नफरत वाले भाषणों का -किसी विशेष समूह के प्रति घृणा के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि बहुलतावाद के लिए प्रतिबद्ध राजनीति में, घृणा फैलाने वाला भाषण लोकतंत्र में किसी भी वैध तरीके से योगदान नहीं कर सकता और वास्तव में यह समानता के अधिकार को खारिज करता है। सर्वोच्च अदालत ने अपने उस फैसले में यह टिप्पणी की, जिसमें उसने 15 जून को एक शो के दौरान सूफी संत खजाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर टीवी एंकर अमीश देवगन के खिलाफ दर्ज कई प्रार्थमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया।



पंचायतों में 14 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच पेयजल स्रोतों की स्वच्छता का होगा सर्वे, विभागीय आदेश जारी

पटना। बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में पेयजल स्रोतों की स्वच्छता (सैनेटरी) सर्वे होगा। पंचायती राज विभाग के माध्यम से यह सर्वे 14 दिसंबर से पांच जनवरी के बीच संपन्न कराया जाएगा। इसको लेकर पंचायती राज और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का संयुक्त आदेश जारी हुआ है। सर्वे में ऐसे कारकों की पहचान की जाएगी, जिससे पेयजल दूषित होते हैं और इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या खड़ी होती है। ऐसे कारकों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाना हो, इस सर्वे का मकसद है। इस दौरान नल-जल योजना, कुआं तथा चापाकलों आदि का सर्वे होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि जहां भी पेयजल स्रोत हैं, वहां की साफ-सफाई कैसी है। नल-जल योजना में पाइप लीकेज तो नहीं है। पेयजल में किसी प्रकार की

गंदगी तो नहीं मिल रही है? चापाकल, नल तथा बोरिंग के आसपास साफ-सफाई कैसी है। सर्वे के लिए एप तैयार किया गया-सर्वे को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचडी) द्वारा मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिस पर सर्वे रिपोर्ट अपलोड भी किया जाएगा। सर्वे में किन-किन बातों का ध्यान रखा है और किस प्रकार रिपोर्ट

तैयार करनी है, इसको लेकर सभी तकनीकी सहायकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण 11 दिसंबर को दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता सर्वे की मुख्य रूप से मॉनिटरिंग करेंगे। तकनीकी सहायक करेंगे सर्वे का काम पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक अपने-अपने क्षेत्र के सभी पंचायतों में यह सर्वे करेंगे। गौरतलब हो कि राज्य के ग्राम पंचायतों के एक लाख 14 हजार वार्डों में नल-जल योजना चल रही है। इनमें 58 हजार वार्डों में नल-जल योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग तथा 56 हजार वार्डों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग करा रहा है। इसके अलावा आठ लाख से अधिक चापाकल लगे हैं।



उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के दूसरे लेन पर मार्च 2022 से आवाजाही शुरू

पटना। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के दोनों लेन मार्च 2022 तक चालू हो जाएंगे। जबकि गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले चार लेन के नए पुल का निर्माण भी जल्द ही शुरू होगा। नेशनल हाइवे की परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडेय ने इन परियोजनाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी सेतु के एक लेन से अभी परिचालन शुरू है। दूसरे लेन को तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है। दूसरे लेन यानी पूर्वी छोर के जीपीओड्रा का काम मार्च 2022 तक पूरा कर दोनों लेन को चालू कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार ने गांधी सेतु के समानांतर चार लेन का नया पुल बनाने का निर्णय लिया है। इसकी निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस नए पुल का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाए। बैठक में पीएम पकेज

के अधीन राज्य की सड़क निर्माण की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। फुलौत और भागलपुर में पुल निर्माण जल्द शुरू होगा राष्ट्रीय उच्च पथ 106 में कोसी नदी पर फुलौत में स्वीकृत पुल और भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर गंगा नदी पर स्वीकृत नए पुल का निर्माण भी जल्द ही शुरू करने का निर्देश दिया गया। इन दोनों पुलों की निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। केवल कार्यात्मक ही करना है। एनएच 104 और 106 में चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाकर जल्द पूरा करने को कहा। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से स्वीकृत सभी 15 आरओबी के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को रेलवे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दूर करने एवं योजनाओं को समय सीमा के अधीन पूर्ण करने को कहा गया।

नई दिल्ली। लक्षणों के आधार पर कोरोना के रोगियों की पहचान मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एपिडेमोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित एक शोध में यह दावा किया गया है। दिल्ली के एक अस्पताल में हुए इस शोध में कहा गया है कि कोरोना निगेटिव एवं पॉजीटिव रोगियों के लक्षण एक समान थे। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी विभाग के निदेशक प्रोफेसर जुगल किशोर के नेतृत्व में हुए शोध में दक्षिणी दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कोरोना के पॉजीटिव एवं निगेटिव रोगियों पर यह अध्ययन किया गया। इसमें 103 पॉजीटिव एवं 103 निगेटिव मरीजों को शामिल कर उनके लक्षणों का व्यापक अध्ययन किया गया। शोध के अनुसार, दोनों समूहों में बुखार, कमजोरी, खांसी, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ, डायरिया, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी होने, सिर दर्द तथा भ्रम के लक्षण पाए गए थे। यह जरूर था कि जो

कोरोना पॉजिटिव-निगेटिव रोगियों में लक्षण एक समान, पहचान संभव नहीं-स्टडी

कोरोना संक्रमित थे, उनमें इन लक्षणों के शिकार ज्यादा लोग थे और निगेटिव लक्षण वाले मरीजों में अपेक्षाकृत कम। इसी प्रकार कोरोना पॉजीटिव में 24 और निगेटिव में 65 लोग ऐसे थे, जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए। प्रोफेसर



किशोर के अनुसार दोनों समूहों में एक-दो मरीज ऐसे भी थे, जिन्होंने सूंघने की शक्ति के ह्रास की भी शिकायत की। शोध के अनुसार, दोनों समूहों में समान लक्षण होने के कारण बिना टेस्ट के कोरोना मरीज की पहचान और इलाज संभव नहीं है। दूसरे, इस पूरे अध्ययन में यदि किसी व्यक्ति के कोरोना मरीज होने की संदेह की पुष्टि करने वाला यदि कोई तथ्य है तो वह पेशा और संपर्क का है। यदि लक्षण वाले किसी व्यक्ति की हिस्ट्री कोरोना मरीज के संपर्क में आने की है या वह स्वास्थ्य पेशेवर है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपरोक्त लक्षण पाए जाने पर वह कोरोना रोगी हो सकता है। यह शोध कोरोना उपचार में टेस्ट की अनिवार्यता को दर्शाता है। जबकि कोई बीमारी अस्तित्व में आ जाती है तो लक्षणों के आधार पर उपचार उपचार होने लगता है, लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा होता नहीं दिख रहा है।

भारत ने किए कोरोना वैक्सीन की सबसे ज्यादा खुराक के करार, फिर भी 60 प्रतिशत आबादी को ही टीका

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वैक्सीन अभी भले ही नहीं आई हो लेकिन टीके के प्री-ऑर्डर बुक करने वाले देशों में भारत सबसे आगे है। वैक्सीन लॉन्च एंड स्केल स्पीडोमीटर की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसके अनुसार, कोरोना के टीके के लिए भारत ने करीब 160 करोड़ खुराक का प्री-ऑर्डर दिया है। इससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिल सकेगा यानी करीब 60 फीसदी आबादी को टीका लगेगा। हालांकि, यह हर्ड इम्युनिटी विकसित करने के लिए काफी होगा। विश्लेषण के मुताबिक, भारत ने 30 नवंबर तक तीन वैक्सीन की 160 करोड़ खुराक के लिए करार किए हैं। वहीं, उसके बाद यूरोपीय संघ ने 158

करोड़ और अमेरिका ने 100 करोड़ से कुछ ज्यादा खुराकों के करार किए हैं। किससे कितनी खुराक-अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी के मुताबिक, भारत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजेनका के कोवैशिल्ड वैक्सीन की करीब 50 करोड़ खुराक खरीदने का करार किया है। वहीं, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स से 100 करोड़ और रूस के गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट से स्मूतनिक-डू वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक मिलेंगी। इसके अलावा भारतीय कंपनियों भी वैक्सीन तैयार करने में जुटी हैं। छोटे देशों ने दिए बड़े ऑर्डर-कई देशों ने अपनी आबादी से ज्यादा वैक्सीन के लिए

| किस देश का कितने वैक्सीन का प्री-ऑर्डर | कितने खुराक |
|--|-------------|
| भारत | 160 करोड़ |
| यूरोपीय संघ | 158 करोड़ |
| अमेरिका | 101 करोड़ |
| कोवैक्स | 70 करोड़ |
| कनाडा | 36 करोड़ |
| ब्रिटेन | 36 करोड़ |
| जापान | 29 करोड़ |
| ब्राजील | 19 करोड़ |

प्री-ऑर्डर बुक किए हैं। एक अनुमान के मुताबिक, कनाडा ने अपनी आबादी से 527 फीसदी ज्यादा वैक्सीन बुक कर ली है। वहीं ब्रिटेन ने 288 फीसदी, ऑस्ट्रेलिया ने 266 फीसदी, चिली ने 223 फीसदी, यूरोपीय संघ ने 199 प्रतिशत और अमेरिका ने लगभग 169 फीसदी और जापान ने 115 फीसदी वैक्सीन के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिए हैं। इसके पीछे की

वजह यह है कि यदि कोई वैक्सीन नाकाम रही और उसे किन्हीं कारणों से अनुमति नहीं मिली तो भी देश की आबादी वैक्सीन से वंचित न रह जाए। गरीब देश डब्ल्यूएचओ पर निर्भर-ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च आय वाले देशों ने लगभग 390 करोड़ डोज बुक कर ली है। मध्यम आय वाले देशों ने 100 करोड़ खुराक और निम्न आय वाले देशों ने करीब 170 करोड़ खुराक हासिल करने के करार किए हैं। शोधकर्ताओं की मानें तो कम आय वाले या गरीब देशों ने सीधे तौर पर कोई करार नहीं किया है। यानी दुनिया की 20 फीसदी आबादी पूरी तरह से कोवैक्स पर निर्भर है।

दरअसल, कोवैक्स गावो, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सीडीपीआई का समन्वित समूह है, जिसका मकसद है कि वह कि जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते, उन तक भी इसे पहुंचाया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंतित-विश्व स्वास्थ्य संगठन बड़े देशों द्वारा टीकों की प्री-बुकिंग पर चिंता जाहिर कर चुका है। संगठन प्रमुख टेड्रोस गेब्रेयेसस के अनुसार, कोविड-19 के उपचार या वैक्सीन का अधिकार सिर्फ कुछ चुने हुए समृद्ध देशों के पास नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी देशों से मिलकर काम करने का आह्वान करते हुए कहा कि कुछ लोग सभी देशों में टीकाकरण में शामिल हों, न कि कुछ देशों में सभी लोग।

संपादकीय

तेल की बढ़ती कीमतें

पेट्रोल की कीमत दो साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, तो यह अभी बहुत चिंता की न सही, लेकिन विचार की बात जरूर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों बैंक दरों में कोई बदलाव न करते हुए यह जाहिर कर दिया था कि वह बढ़ती महंगाई को रोकने के पक्ष में नहीं है और अब तेल कंपनियों द्वारा लगातार कीमत में बढ़ोतरी यह बता रही है कि केंद्र सरकार भी अभी महंगाई के प्रति गंभीर नहीं है। तभी तो लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। सोमवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 83.71 रुपये प्रति लीटर हो गई। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार, डीजल की कीमत भी संशोधित करते हुए 73.87 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। दिल्ली में सितंबर 2018 में पेट्रोल-डीजल की कीमतें इसी ऊंचाई पर थीं। करीब दो महीने के बाद तेल कंपनियों ने 20 नवंबर से तेल की कीमतों में दैनिक संशोधन शुरू किया है और असर साफ दिख रहा है। पिछले 16 दिनों में ही पेट्रोल की कीमत 2.37 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3.12 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। गौर करने की बात है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 90.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 80.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है। कोलकाता व चेन्नई में भी पेट्रोल-डीजल की कीमत में दिल्ली के मुकाबले ज्यादा वृद्धि दिख रही है। सरकारी नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम व हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और विदेशी विनिमय दर के आधार पर प्रतिदिन पेट्रोल व डीजल की दरों में संशोधन करती हैं। इन कंपनियों को दी गई इस ताकत के बावजूद केंद्र सरकार की अपनी भूमिका है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। वैसे आज सरकार के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना मजबूरी भी है, क्योंकि कोरोना के समय में उसकी कमाई घटी है और विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए धन चाहिए। पेट्रोल-डीजल से मिलने वाले राजस्व से सरकार को बल मिलता है। चूंकि नया टैक्स लगाना आसान नहीं, उसमें अलोकप्रियता का खतरा होता है, इसलिए सरकार को पेट्रोल-डीजल के जरिए कमाई ज्यादा मुफ्दी लगती आई है। जैसे-जैसे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ते हैं, वैसे-वैसे सरकार की कमाई भी बढ़ती है। किसानों और उत्पादकों को बल देने के लिए भी महंगाई को जरूरी बताया जा रहा है। कोरोना के प्रभाव में एक समय ऐसा आ गया था, जब रोजमर्रा के सामान की कीमतें घटने लगी थीं। खुदरा मूल्य अलाभकारी होने लगे थे। ऐसे में, महंगाई बढ़ने देना आर्थिक सुधार का एक उपाय है। हालांकि, यह विशेष चिंता का विषय है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से असली उत्पादकों व किसानों को कितना लाभ होगा? इस पर सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ने की वजह से तेल कंपनियों को मूल्य में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। ऐसे में, सवाल बड़ा है, कीमत को कहां तक बढ़ने दिया जाएगा? पेट्रोल-डीजल की कीमत अगर ज्यादा बढ़ेगी, तो जाहिर है, महंगाई को सीधे बल मिलेगा, लेकिन सरकार को देखना होगा कि कोरोना व लॉकडाउन से त्रस्त लोग महंगाई को किस हद तक झेलने की स्थिति में हैं। लगे हाथ, सबको यह भी सोच लेना चाहिए कि भारत बंद से महंगाई घटेगी या बढ़ेगी।



आज के ट्वीट

स्थिति

रियल एस्टेट सेक्टर की वया स्थिति थी इससे हम मालीभाति परिचित है। घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी। कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को पेशान करके रखा था: PM

ज्ञान गंगा

आचार्य रजनीश ओशो/ में एक आदमी को देखा जो ग्यारह वर्षों से खड़ा हुआ है। उनका नाम ही खड़ेश्री बाबा हो गया है। मैंने पूछा, लेकिन इस आदमी पर क्या मुसीबत आ पड़ी? यह खड़ा क्यों हो गया? मेरे ड्राइवर एक सरदार जी थे, बड़े ज्ञानी थे। गाड़ी कम चलाते थे, जपूजी ज्यादा पढ़ते थे। बोले कि कुछ नहीं हुआ, इसकी पत्नी ने इससे कहा खड़े रहो और खुद किसी दूसरे पति के साथ भाग गयी। तब से यह बेचारा खड़ा है। अब कोई इसको बिटोए तो बेटे। धर्म धर्म है, उसका पालन तो करना ही पड़ता है। पत्नी किसी और को अत्यास करवा रही होगी धर्म का, आध्यात्मिक का। यह बेचारा यही अत्यास कर रहा है। खड़ा हुआ है। इमेन्युअल कांट के लिए मैं कोई आलोचना नहीं करता, लेकिन तुमसे मैं यह कहता हूँ कि अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रकाश की जरा सी भी किरण दिखाई पड़े, सुगंध की कोई जरा सी झोंक, तो वही दिशा है, वही मार्ग है। फिर हिम्मत करना, फिर रुकना मत। सोचने का काम बाद में कर लेंगे। और यह मंत्र अनुभव है कि जो इस रास्ते पर बड़े हैं, उन्होंने फिर सोचने की कोई जरूरत नहीं समझी। क्योंकि हर अनुभव और गहरा होता गया। हर अनुभव नई छलांग, नई चुनौती और नये परिवर्तन और नई-नई क्रांति पर ले जाता रहा। तो जो तुम्हें हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। सोचो मत। सोचने से रुक जाओ। क्योंकि जीवन के सारे गहरे अनुभव हृदय से होते हैं, बुद्धि से नहीं होते। और सोचना बुद्धि से होता है। और बुद्धि और हृदय का कोई मेल नहीं बैठता तो बुद्धि तुम्हें पागल कहेगी कि यह क्या पागलपन है कि शरीर में झुरझुरी आ रही है। जाओ किसी डाक्टर को दिखाओ। यह क्या पागलपन है? कि अकेले बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे हो। चलो, किसी मनोवैज्ञानिक को दिखा आओ। यह दुनिया बहुत अजीब है। यहां अगर तुम शांति से बैठकर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो हर आदमी टोकेगा। क्यों जी, क्यों फिजूल बैठे हुए हो? शर्म नहीं आती? दुनिया मरी जा रही है और तुम बैठे हो। हजार काम करने को पड़े हैं और तुम बैठे हो। कोई जाकर एडोल्फ हिटलर को नहीं कहता कि तुम क्या कर रहे हो? छह करोड़ लोगों कि हत्या-लेकिन काम बड़ा कर रहा है। अगर तुम बैठे-बैठे गुनगुना रहे हो तो लोग कहेंगे कि जिंदगी बरबाद कर रहे हो। जैसे कि उन्हें जिंदगी मिल गई। बीड़ी पीओ! दम मारो दम! बैठे-बैठे मुस्कुरा रहे हो। किसी ने देख लिया तो नाहक बदनामी होगी अग्रेजी कहावत है, इट इज बेटर टू डू समथिंग देन नथिंग।

अनुभव



इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए.. दुनिया तो भगवान से भी दुखी है..

कानून के समक्ष समता-संरक्षण की मांग



अनूप भटनागर

तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक करार देने वाले उच्चतम न्यायालय में अब इस समुदाय में एक से ज्यादा पत्नियों की प्रथा का मुद्दा पहुंचा है। यह मुद्दा मुख्य रूप से पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करने को दंडनीय अपराध बनाने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के एक अंश से जुड़ा हुआ है। न्यायालय के समक्ष सवाल रखा गया है कि देश में दंडनीय कानून में क्या इस तरह का प्रावधान किया जा सकता है जो विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव करता हो या जो एक वर्ग के कृत्य के लिये दंडनीय हो और दूसरे वर्ग के लिये दंडनीय नहीं हो। सवाल यह उठाया गया है कि अगर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत हिन्दू, ईसाई, पारसी

और सिख द्वारा अपनी पत्नी के जीवनकाल में दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध है तो फिर मुस्लिम समुदाय को इसके दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के बारे में न्यायिक व्यवस्था का सवाल है तो उच्चतम न्यायालय ने मई 1995 में कहा था कि अगर हिन्दू पति अपनी पत्नी को तलाक दिये बगैर ही इस्लाम धर्म स्वीकार करके दूसरी शादी करता है तो ऐसी शादी अमान्य होगी और ऐसा करने वाला हिन्दू पति धारा 494 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी होगा। धारा 494 के तहत इस तरह का विवाह दंडनीय अपराध है, जिसके लिये दस साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। याचिका के अनुसार, धार्मिक परंपरा के आधार पर किसी भी अनुसूचित कृत्य में भेदभाव नहीं किया जा सकता

अनुसूचित धारा 494 धर्म के आधार पर भेदभाव करती है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) का उल्लंघन होता है। संविधान का अनुच्छेद 14 समता के अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। इसी तरह, अनुच्छेद 15 (1) के अंतर्गत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। न्यायालय से संविधान में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर नागरिकों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने संबंधी प्रावधानों का हवाला देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के एक हिस्से को निरस्त करने का अनुरोध किया है, शीर्ष अदालत ने न्याय

के हित में धारा 494 की व्याख्या करते हुए कहा था कि दोनों समुदायों की तरह ही कानून की दोनों व्यवस्थाओं के बीच सद्भाव बना रहना चाहिए। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि उसकी व्याख्या का तात्पर्य यह है कि हिन्दू कानून और मुस्लिम कानून एक-दूसरे समुदाय के कानूनों में हस्तक्षेप के बगैर अपने दायरे में ही काम करेंगे। न्यायालय ने यह भी कहा था कि इस्लाम का मकसद या जागरूक मुस्लिम समुदाय की मंशा यह नहीं है कि हिन्दू पतियों को सिर्फ दोबारा शादी के लिये मुस्लिम बनने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बहरहाल, बहु-विवाह पद्धति को आधार बनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के वाक्यों की रचना पर सवाल उठाये गये हैं, अब देखना यह है कि इस संवेदनशील मामले में शीर्ष अदालत क्या रुख अपनाती है लेकिन इतना निश्चित है कि याचिकाकर्ताओं ने धारा 494 और मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 2 के प्रावधानों पर सवाल उठा कर एक नये मुद्दे को जन्म दिया है, जिसका समाधान न्यायालय को ही करना होगा।

भरत झुनझुनवाला

किसानों द्वारा नये कृषि कानून को निरस्त किये जाने की मांग आंशिक रूप से सही है, चूंकि इसके पीछे सरकार की मंशा समर्थन मूल्य को हटाने की दिखती है। सरकार द्वारा दिए गये समर्थन मूल्य से कुछ विशेष फसलें जैसे गन्ना, गेहूं एवं धान से किसानों को उचित दाम मिल जाते हैं। इन समर्थन मूल्यों के चलते किसान इन फसलों का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। उन्हें यह डर नहीं रहता कि बाजार में फसल के दाम गिर जायेंगे और उन्हें नुकसान हो सकता है। कुछ वर्ष पूर्व पालनपुर में किसानों ने अपनी आलू की फसल को सड़कों पर लाकर डम्प कर दिया था। उनका कहना था कि मंडी में आलू के दाम 2 रुपये प्रति किलो रह गये हैं, जिस मूल्य पर आलू को खोदकर मंडी तक पहुंचाने का भी खर्च वसूल नहीं होता है। अतएव अपना क्रोध जताने के लिये उन्होंने आलू को सड़कों पर डाल दिया था। इसी क्रम में कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में ग्वार की फसल ज्यादा होने से किसानों को भारी घाटा लगा था। लेकिन गन्ना, गेहूं एवं धान की फसल में ऐसी परिस्थिति नहीं आती। किसान को निर्धारित मूल्य मिलता ही है, कितना भी उत्पादन बढ़ जाये। समर्थन मूल्य के चलते किसानों को गन्ना, गेहूं एवं धान में इस प्रकार के मूल्य की गिरावट का संदेह नहीं रहता है और उन्हें पर्याप्त लाभ मिल जाता है। किसान की खुशहाली में समर्थन मूल्य की अहम भूमिका है। लेकिन हमारी कृषि सरकारी समर्थन पर खड़ी है, न कि बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा शक्ति पर। जैसे कोई व्यक्ति बैसाखी पर चलता है, उसी प्रकार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान समर्थन मूल्य की बैसाखी पर आश्रित हैं। विदित हो कि इस समर्थन मूल्य का जो भार होता है, वह अंततः आम आदमी पर पड़ता है। जैसे यदि बाजार में गेहूं का दाम 12 रुपये प्रति किलो हो और समर्थन मूल्य 17 रुपये प्रति किलो हो तो 5 रुपये प्रति किलो का अतिरिक्त मूल्य फूड कारपोरेशन द्वारा किसान को भुगतान किया जाता है। यह रकम अंततः सरकार द्वारा फूड कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जाती है और सरकार द्वारा जनता पर टैक्स लगाकर वसूल की जाती है। इस प्रकार किसान की खुशहाली अंततः आम आदमी से टैक्स वसूल करके टिकी हुई है। फिर भी समर्थन मूल्य का सार्थक परिणाम है कि आज किसान पर्याप्त मात्रा में गन्ना, गेहूं एवं धान का उत्पादन कर रहे हैं और हम भुखमरी से बचे हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था पर यह एक बोझ बन रहा है क्योंकि किसानों को बाजार से अधिक मूल्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा जनता से टैक्स वसूल किया जा रहा है। फूड कारपोरेशन की अकुशलता एवं संभावित भ्रष्टाचार का बोझ भी जनता पर ही पड़ता है। इसके अलावा गन्ना, गेहूं एवं धान का निर्धारित मूल्य मिलने के कारण किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार के सामने दोतरफा चुनौती है। समर्थन मूल्य के बावजूद किसानों की आय में वृद्धि बहुत ही कछुआ चाल से हो रही है। सेंटर फार मानिट्रिंग ऑफ



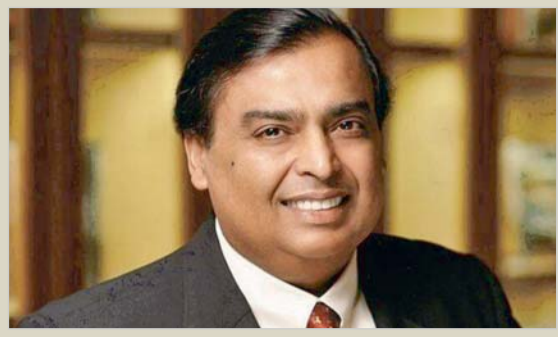
इंडियन इकॉनमी के अनुसार वर्ष 2013 से 2019 के बीच देश के किसानों की आय में मात्र 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि सरकार का लक्ष्य इन्हीं वर्षों में इसे दोगुना यानी 100 प्रतिशत वृद्धि का था। एक तरफ किसानों की आय में वृद्धि नहीं हो रही है और दूसरी तरफ सरकार पर समर्थन मूल्य का बोझ पड़ रहा है। इन दोनों समस्याओं का हल उत्पादन बढ़ाकर हासिल नहीं हो सकता। सरकार ने सिंचाई के विस्तार, फर्टिलाइजर के सही उपयोग, ड्रोन से रोगों की पहचान, आदि तमाम सुधार कृषि क्षेत्रों में किये हैं जो कि सराहनीय हैं लेकिन इन प्रयासों का अंतिम परिणाम उत्पादन में वृद्धि है जो कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसान के लिए हानिप्रद हो सकता है, जैसा कि पालनपुर के किसानों को आलू के अधिक उत्पादन करने पर मुंह की खानी पड़ी थी। हमें इस मसले पर दूसरी तरफ से सोचना पड़ेगा। हमें दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए। आज नीदरलैंड एक छोटा-सा देश एक वर्ष में 2500 करोड़ रुपये के ट्यूलिप फूलों का निर्यात करता है। इटली और ट्यूनिशिया जैतून का सम्पूर्ण विश्व को निर्यात करते हैं। फ्रांस द्वारा विशेष गुणवत्ता के अंगूर का उत्पादन कर उससे शराब बनाकर सम्पूर्ण विश्व को निर्यात की जाती है। अमेरिका से सेब और अखरोट का सम्पूर्ण विश्व को निर्यात हो रहा है। दक्षिण अमेरिका के पनामा से केले, वियतनाम से काफी और मलेशिया से रबर का भारी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। इन तमाम देशों ने किसी विशेष फसल में अपनी महारत हासिल करके उस फसल के वैश्विक बाजार में अपनी पैठ बना ली है और उस विशेष फसल का निर्यात करके वे भारी रकम कमा रहे हैं। अतः हमें भी ऐसी फसलों की खोज करनी चाहिए, जिन फसलों पर हम वैश्विक बाजार में अपनी सुदृढ़ पैठ बना सकें। उन फसलों की गुणवत्ता अन्य सभी

देशों की तुलना में अच्छी और दाम कम होने चाहिए, जिससे हम प्रतिस्पर्धा में खड़े रह सकें। हमारे देश का सौभाग्य है कि यहां हर प्रकार की जलवायु बारहों माह उपलब्ध रहती है। जैसे सर्दियों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र का तापमान कम रहता है तो गर्मी में हिमालयी राज्यों का तापमान कम रहता है। हम सम्पूर्ण विश्व को बारहों महीने गुलाब, ग्लाडोलेस और ट्यूलिप जैसी फसलें उपलब्ध करा सकते हैं। पूर्वोत्तर देशों में ऑर्किड नाम के फूल होते हैं, जिनका सम्पूर्ण हिमालयी क्षेत्र में उत्पादन किया जा सकता है। इस फूल की एक छड़ी 5000 रुपये तक बिकती है। हमारे सामने चुनौती है कि हम अपनी जलवायु की विविधता का लाभ उठाकर ऐसी फसलों पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, जिनका हम पूरे वर्ष उत्पादन करके निर्यात कर सकें। तब हम अपने किसानों को ऊंची आय उपलब्ध करा सकेंगे। आज नीदरलैंड, इटली, फ्रांस और अमेरिका के खेत श्रमिकों को लगभग 8 हजार रुपया प्रतिदिन का वेतन इन्हीं फसलों के उत्पादन में मिल रहा है। यदि हम इन विशेष फसलों के उत्पादन और निर्यात पर ध्यान दें तो हम भी अपने खेत श्रमिकों को 8 हजार रुपये प्रतिदिन की आय उपलब्ध करा सकते हैं। दुर्भाग्य है कि हमारी यूनियनवादी और प्रयोगशालाएं इतनी लचर हैं कि वे इस प्रकार के कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पा रही हैं। इनके वैज्ञानिकों को वास्तव में रिसर्च करने में कोई रुचि नहीं है, जिसके कारण आज सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र संकट में है और हमारे किसान समर्थन मूल्य की बैसाखी को बनाये रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जलवायु से धनी भारतवर्ष द्वारा वैश्विक स्तर की उच्च मूल्य को फसलें उगाकर विश्व बाजार में पैठ बनाई जा सकती है।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

आज का राशिफल

| | |
|----------------|---|
| मेष | बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। |
| वृषभ | सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। वाणी की सोम्यता आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। धन लाभ के योग हैं। |
| मिथुन | जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। किसी मित्र या रिश्तेदार से धन लाभ के योग हैं। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे। |
| कर्क | संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है। |
| सिंह | पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता से तनाव मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। |
| कन्या | आर्थिक योजना फलदायी होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। भारी व्यय की संभावना है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। |
| तुला | जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। विरोधी परास्त होंगे। |
| वृश्चिक | बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। क्रिया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाद-विवाद की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी। |
| धनु | व्यावसायिक योजना सफल होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। क्रिया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाद-विवाद की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी। |
| मकर | पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। अनावश्यक व्यय हो सकता है। |
| कुम्भ | प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी। |
| मीन | रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जनों से पीड़ा मिलेगी। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। |



डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत की ताकत, 2021 में 5जी क्रांति लेकर आएगा जियो-मुकेश अंबानी

बिजनेस डेस्क। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी जियो 2021 में 5जी क्रांति लेकर आएगी। अंबानी ने मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 30 करोड़ फोन ग्राहक अभी 2जी में 'फसे' हुए हैं। उन्हें स्मार्टफोन में लाने के लिए नीतिगत कदमों की जरूरत है।

आज डिजिटल से जुड़ा है देश: अंबानी
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भारत की ताकत है। आज दुनिया में भारत सबसे बेहतर तरीके से 'डिजिटल से जुड़ा' देश है। डिजिटल सुधार से भारत में जीवन स्तर बेहतर हुआ है। देश में आज भी ग्राहकों को स्मार्टफोन में लाने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। स्मार्टफोन के जरिये ये ग्राहक भी डिजिटल लेनदेन में सक्षम हो सकेंगे। इसके अलावा देश में 5जी नेटवर्क को तेजी से लगाने की जरूरत है।

हम आयात के भरोसे नहीं रह सकते: अंबानी
उद्योगपति ने कहा कि उनकी कंपनी जियो देश में 5जी क्रांति की अगुवाई करेगी। भारत को सेबीकंडक्टर के विनिर्माण केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम बड़े आयात पर निर्भर नहीं रह सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत आने वाले दिनों में सेमी कंडक्टर का मैनुफैक्चरिंग हब बन सकता है। हम सेमी कंडक्टर के लिए केवल आयात के भरोसे नहीं रह सकते हैं।

उतार-चढ़ाव के बीच 182 अंक चढ़े सेंसेक्स, निपटी 13,393 पर बंद

मुंबई। घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार-चढ़ाव के बीच कारोबार हुआ, लेकिन सत्र के आखिर में सेंसेक्स 181.54 अंकों यानी 0.40 फीसदी की बढ़त के साथ 45,608.50 पर बंद हुआ, जबकि कारोबार के दौरान सेंसेक्स रिकॉर्ड 45,742.23 तक उछला। निपटी भी 37.20 अंकों यानी 0.28 फीसदी की तेजी के साथ 13,392.95 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)के 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स बीते सत्र के मुकाबले बढ़त के साथ 45,568.80 पर खुला और 45,742.23 तक उछला जोकि सेंसेक्स का अब तक का रिकॉर्ड स्तर है जबकि दिनभर के कारोबार के दौरान इसका निचला स्तर 45,335.17 रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक बीते सत्र के मुकाबले तेजी के साथ 13,393.85 पर खुला और 13,435.45 तक चढ़ा जबकि दिनभर के कारोबार के दौरान इसका निचला स्तर 13,311.05 रहा। हालांकि बीएसई मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 28.83 अंक फिसलकर 17,525.28 पर बंद हुआ और स्मॉलकैप सूचकांक बीते सत्र से 51.05 अंकों की गिरावट के साथ 17,491.61 रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 शेयर तेजी के साथ बंद हुए जबकि 14 शेयरों में गिरावट रही। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच शेयरों में अल्ट्राटेक सीमेंट (3.15 फीसदी), टीसीएस (2.21 फीसदी), रिलायंस (1.82 फीसदी), एचसीएलटेक (1.06 फीसदी), इन्फोसिस (0.80 फीसदी) शामिल रहे। सेंसेक्स के सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच शेयरों में सनफार्मा (2.36 फीसदी), इंडसइंड बैंक (2.00 फीसदी), एनटीपीसी (1.55 फीसदी), एशियन पेंट (1.38 फीसदी), टेक महिंद्रा (1.38 फीसदी) शामिल रहे। बीएसई के एनजी और आईटी सेक्टरों के सूचकांकों में एक फीसदी से ज्यादा की बढ़त रही जबकि टेलीकॉम में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट रही।



5जी की समय पर लॉन्चिंग करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत : मोदी



नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार के साथ-साथ दूरसंचार क्षेत्र के सभी हितधारकों को पांचवीं पीढ़ी 5जी प्रौद्योगिकी की समय पर लॉन्चिंग सुनिश्चित करने के लिए



भारत 2-3 साल में 5जी के उपयोग के लिए पूरी तरह हो जाएगा तैयार : मित्तल

नई दिल्ली। भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल ने मंगलवार को कहा कि अगले 2 से 3 सालों में भारत 5जी प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि इतने समय में 5जी देशभर में टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए एक मानक बन जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि 2 या 3 साल में भारत उन सभी निवेशों का लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा जो दुनिया ने 5जी मानक और 5जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए हैं। साथ ही कहा कि अगले कुछ सालों में इनके उपकरणों की कीमतों में भी कमी आएगी और उपकरणों की उपलब्धता भी सहज होगी। उन्होंने आगे कहा, कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमने आज हासिल कर लिया है लेकिन शायद उन्हें हम कई साल तक नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन महामारी के कारण बड़े पैमाने पर हुआ असर हमारे देश के डिजिटलाइजेशन के लिए एक वरदान है। भारतीय एयरटेल के उद्योग और ब्रांडबैंड सहित कई नए क्षेत्रों में प्रवेश को लेकर मित्तल ने कहा कि कंपनी भारतनेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए तत्पर है।

मिलकर काम करना होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) को संबोधित करते हुए, मोदी ने भारत को दूरसंचार उपकरण, डिजाइन डेवलपमेंट और विनिर्माण के लिए वैश्विक हब बनाने के लिए एक साथ काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, आइए हम भारत को दूरसंचार उपकरण, डिजाइन, विकास और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह मोबाइल तकनीक की वजह से है, जिससे लाखों भारतीयों को अरबों डॉलर का लाभ हुआ। उन्होंने कहा कि मोबाइल तकनीक की वजह से सरकार महामारी के दौरान गरीबों और कमजोरों की जल्द मदद कर सकी। प्रधानमंत्री ने उद्योग के प्रतिभागियों से कहा, यह मोबाइल प्रौद्योगिकी के कारण ही है कि हम अरबों कैशलेस लेनदेन देख रहे हैं जो औपचारिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। यह मोबाइल प्रौद्योगिकी के कारण ही है कि हम टोल बूथों पर सहज संपर्क रहित इंटरफेस कर पाएंगे। महामारी और लॉकडाउन के बीच, दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के दिग्गजों की तारीफ करते हुए मोदी ने कहा कि यह उद्योग और इसके नवाचारों के प्रयासों के कारण ही था कि दुनिया महामारी के दौरान भी काम कर रही थी, जिसमें कनेक्टिविटी, शिक्षा और व्यवसाय और अन्य संचालन शामिल थे।

भारत पेट्रोलियम के निजीकरण के बाद भी LPG ग्राहकों को मिलती रहेगी सब्सिडी, बनेगी अलग इकाई

नई दिल्ली।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण के बाद भी उसके 7.3 करोड़ घरेलू रसोई गैस ग्राहकों को सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। कंपनी के एलपीजी कारोबार के लिये एक अलग रणनीतिक कारोबारी इकाई (एसबीयू) बनाने की योजना है। बीपीसीएल के नये मालिक को अधिग्रहण के तीन साल बाद ही कंपनी के एलपीजी कारोबार को अपने पास बनाये रखने अथवा बेचने का अधिकार होगा। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

निजीकरण के बाद भी सब्सिडी जारी
अधिकारी ने कहा कि तीन साल बाद भी यदि बीपीसीएल का नया मालिक एलपीजी कारोबार को कंपनी में ही बनाए रखना चाहेगा तो उसके बाद भी ग्राहकों को सरकारी सब्सिडी मिलती रहेगी। यदि नया मालिक एलपीजी कारोबार को रखने से मना करता है तो तीन साल बाद उसके एलपीजी ग्राहकों को अन्य दो सरकारी कंपनियों इंडियन ऑयल कारपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि सरकार कंपनी के 7.3 करोड़ ग्राहकों को निजीकरण के बाद भी



सब्सिडी जारी रखेगी। लेकिन किसी निजी कंपनी को सरकारी सब्सिडी देने में हितों के टकराव के चलते एलपीजी कारोबार को एक अलग एसबीयू के तहत रखा जायेगा।

एसबीयू खातों का ऑडिट
उन्होंने कहा कि एसबीयू अलग से खातों का विवरण रखेगी। साथ ही उसे कितनी सब्सिडी मिली और डिजिटल तरीके से उसने कितने ग्राहकों को सब्सिडी भेजी इसका भी ब्यौरा उसे रखना होगा। कोष की हेरा-फेरी नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए एसबीयू खातों का ऑडिट भी कराया जाएगा। निजीकरण के बाद भारत पेट्रोलियम को सब्सिडी देने का यह मतलब नहीं होगा कि अन्य निजी एलपीजी वितरकों को भी सब्सिडी दी जाएगी। अधिकारी

ने कहा, 'भारत पेट्रोलियम एक पुरानी कंपनी है और इस तरह रातोंरात उसके ग्राहकों की सब्सिडी को खत्म नहीं किया जा सकता।%

नई कंपनी पर तीन साल तक पाबंदी
उन्होंने कहा कि भारत पेट्रोलियम से सरकार के निकलने के बाद भी नई कंपनी पर तीन साल तक पाबंदी रहेगी। कंपनी की नयी मालिक किसी परिपक्वता को बेच या हस्तांतरित नहीं कर सकेगी। तीन साल बाद उसके पास एलपीजी कारोबार को रखने या बेचने का अधिकार होगा। सरकार साल में 12 रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी सिलेंडर) सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। इस महीने प्रत्येक सिलेंडर पर 50 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। इसे सीधे ग्राहकों के खातों में पहुंचा दिया जाएगा।

कोरोना को मात देकर आगे बढ़ता चीन



बीजिंग।

अचानक से फैली कोरोना महामारी के खिलाफ, करोड़ों चीनी लोगों ने सीपीसी सेंट्रल कमिटी के मजबूत नेतृत्व में कोरोनावायरस के खिलाफ एक जबरदस्त जंग शुरू की, जो कि मानव इतिहास में बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक और शानदार उपलब्धि है। इसके अलावा, चीन ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने की एक महान भावना का निर्माण किया, जिसमें लोगों के जीवन को पहले रखना, राष्ट्रव्यापी एकजुटता, बलिदान, विज्ञान का सम्मान करना और मानवता की भलाई की भावना शामिल है।

दरअसल, चीन कोविड-19 महामारी के बाद से विकास की ओर लौटने वाली पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है और महामारी की रोकथाम और आर्थिक सुधार दोनों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जो देश की शासन प्रणाली की उत्कृष्ट दक्षता को प्रदर्शित करता है। अदृश्य साहस के साथ चीनी लोगों ने कोरोनावायरस को मात दी और इतिहास में एक शानदार अध्याय लिखा। इतना ही नहीं, कोरोना काल में चीन में डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हुआ है। 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट सीटी, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन चिकित्सा आदि नयी तकनीकों और नये मॉडों का तेज विकास हुआ है, जिससे देश के आर्थिक विकास में जीवन शक्ति संचार हुई है। जाहिर है, चीन ने विपत्तियों को अवसर में परिवर्तित किया है। चीन के पास और अधिक विकास हासिल करने का आत्मविश्वास और शक्ति है। साधनहीन देश से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला चीन पहले अपने पैरों पर खड़ा हुआ, फिर समृद्ध हुआ और उसके बाद मजबूत हुआ। पिछले 71 वर्षों के बाद, खास तौर पर चीन में सुधार और खुलेपन की नीति लागू होने के

बाद चीन ने अपने लोगों पर भरोसा करते हुए असंभव कार्य को संभव बना दिया है, और आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता में तेजी लाने का चमत्कार किया है। आज, चुनौतियों से निपटने के लिए देश की शक्तिशाली व्यापक राष्ट्रीय शक्ति उसका आत्मविश्वास ही है। इसके संस्थागत लाभ जोखिम से निपटने के लिए एक बुनियादी गारंटी के रूप में काम करते हैं। अगले साल से चीन 14वीं पंचवर्षीय योजना की आगामी अवधि में एक नए विकास चरण में प्रवेश करेगा। यद्यपि बाहरी वातावरण में गहरा और जटिल परिवर्तन हो रहा है, फिर भी चीन की अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर दीर्घकालिक विकास की मूल प्रवृत्ति अपरिवर्तित बनी हुई है। यह अर्थ है कि चीनी विज्ञान आधारित तरीके से विकास की स्थितियों का विश्लेषण करेगा, स्थिरता सुनिश्चित करते हुए प्रगति को आगे बढ़ाने के सामान्य सिद्धांत का पालन करेगा, विकास और सुरक्षा का समन्वय करेगा, नए विकास पैटर्न बनाने में तेजी लाएगा, और विकास को उच्चतर बनाने के लिए काम करेगा। यानी कि चीन हर प्रकार की कठिनाइयों और जोखिमों को दूर करते हुए आगे बढ़ने की राह पर है।

रुपया 30 पैसे उछला

मुंबई। दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर के लुढ़कने और घरेलू शेयर बाजार में रही तेजी के दम पर आज अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया 30 पैसे की छलांग लगाकर 73.60 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। गत दिवस 10 पैसे की गिरावट में 73.90 रुपये प्रति डॉलर पर रहा था। रुपया आज सात पैसे की बढ़त में 73.83 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और यही इसका दिवस का निचला स्तर रहा। कारोबार के दौरान यह 73.59 रुपये प्रति डॉलर के दिवस के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अंत में गत दिवस की तुलना में भारतीय मुद्रा 30 पैसे की तेजी में 73.60 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुई।



वोडा आइडिया को अच्छे दिन की उम्मीद , कहा- सरकार के समर्थन से जल्द ही सफलता की कहानी लिखेंगे

बिजनेस डेस्क।

वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) ने कहा कि दरों, शुल्कों, स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और कीमतों को लेकर कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार के समर्थन और मौजूदा प्रगतिशील नीतियों से दूरसंचार क्षेत्र 'सफलता की कहानी' लिखने में सफल रहेगा। वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रविंद्र टाकर ने कहा कि कई पहलू मसलान भारत-केन्द्रित 5जी का इस्तेमाल, सबसे नीचे के वर्ग या बिना ब्रांडबैंड पहुंच और बिना स्मार्टफोन वाले लोगों तक डिजिटल संपर्क पहुंचाना एक उम्मीद पैदा करता है। टाकर ने कहा कि वीआईएल अपनी दीर्घावधि की प्रतिबद्धता और निवेश के बेहतर रिकॉर्ड के जरिये इन अवसरों का लाभ उठाने की तैयारी है। टाकर ने मंगलवार

को इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ चुनौतियां भी हैं। ये दरों, शुल्कों, स्पेक्ट्रम की उपलब्धता और मूल्य से जुड़ी हैं। सरकार इन चीजों को समझती है और वह एक प्रगतिशील राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति लेकर आई है। अब सरकार इस नीति का क्रियान्वयन कर रही है। वोडाफोन आइडिया के सीईओ ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सरकार के समर्थन से उद्योग और हमारी कंपनी अगले 25 साल तक भी सफलता की कहानी लिखने में सफल रहेगी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में निचले फोन घनत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा



कि ग्रामीण क्षेत्रों में फोन घनत्व सिर्फ 59 प्रतिशत है जबकि शहरों में यह 134 प्रतिशत है। साथ ही उन्होंने कहा कि 45 करोड़ मौजूदा मोबाइल ग्राहक ब्रांडबैंड से नहीं जुड़े हैं या उनके फोन घनत्व का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा

चेन्नई स्थित नोकिया की फैक्ट्री में बन रहे अब लेटेस्ट 5 जी गियर

नई दिल्ली।

फिनिश टेलीकॉम गियर बनाने वाली कंपनी नोकिया ने कहा है कि उसने चेन्नई में अपनी फैक्ट्री में नेक्स्ट-जनरेशन 5जी उपकरण बनाने शुरू कर दिये हैं। देश में 5जी न्यू रेडियो का निर्माण करने वाली इस पहली कंपनी ने अब नोकिया एयरसेल मैसिव मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट (एमएमआईएमओ) सॉल्यूशन को लेकर उत्पादन शुरू किया है। मैसिव एमआईएमओ 5जी

तकनीक का एक सबसे जरूरी ऐप्लीमेंट है। यह उपकरण पहले से ही कई देशों को निर्यात किया जा रहा था, जो 5 जी शुरू करने के अंतिम चरणों में हैं। नोकिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के मार्केट के प्रमुख संजय मलिक ने कहा, हमारी चेन्नई फैक्ट्री भारत की मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं के लिए एक मानक के रूप में उभरी है, जो भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में ऑपरेटरों के लिए टेलीकॉम टेक्नॉलॉजी की एक पूरी श्रृंखला लेकर आई है। साथ ही यह हमें

भारतीय ऑपरेटरों का सपोर्ट करने में भी मदद करेगा क्योंकि वे भी 5 जी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। 2008 में चेन्नई में आने के बाद से नोकिया ने मैनुफैक्चरिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं विकसित करने में 600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इसकी फैक्ट्री और सेटअप 1.4 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। 2022 तक नोकिया भविष्य में उन सर्कल में कई स्पेक्ट्रम बैंड में 3 लाख रेडियो



इकाइयों को तैनात करके भविष्य में 5जी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। नोकिया की नई रिसर्च के मुताबिक 2030 तक 5जी इण्डस्ट्रीज में ग्लोबल जीडीपी में 8 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने की क्षमता है।

भारत बंद से भारत-बांग्लादेश व्यापार रहा बेअसर



अगरतला/इंफाल।

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए विवादामुक्त कृषि कानूनों को लेकर किसान यूनियनों की ओर से मंगलवार को बुलाए गए भारत बंद से पूर्वोत्तर राज्यों के साथ भारत-बांग्लादेश व्यापार अप्रभावित रहा। सीमा शुल्क और चेक-पोस्ट अधिकारियों के अनुसार, त्रिपुरा और मेघालय में एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) और लैंड क्रॉसिंग स्टेशन (एलसीएस) के माध्यम से भारत-बांग्लादेश व्यापार और मौरै आईसीपी (पूर्वी मणिपुर में) के माध्यम से भारत-म्यांमार व्यापार सुचारु रूप से जारी रहा। किसानों की ओर से बुलाए गए भारत बंद के बीच बिना किसी हस्तक्षेप के व्यापार हुआ। अगरतला-अखौरा (बांग्लादेश) आईसीपी पश्चिम बंगाल में पेटापोल-बेनापोल आईसीपी के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बिंदु है। अगरतला-अखौरा आईसीपी के पब धक देबाशीथ नदी ने

आईएमएस को बताया कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार भारत बंद से पूरी तरह अप्रभावित रहा। अगरतला से सटे अगरतला-अखौरा आईसीपी पूर्वोत्तर भारत में सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक भूमि बंदरगाह है, जिसके माध्यम से बांग्लादेश से हर दिन विभिन्न सामानों से भरे औसतन 80 से 100 ट्रक त्रिपुरा पहुंचते हैं। अगरतला-अखौरा आईसीपी के माध्यम से हर दिन औसतन तीन से चार करोड़ रुपये का व्यापार होता है।

सात पूर्वोत्तर राज्यों से सटे भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमा के साथ लगभग 35 ऑपरेशनल लैंड क्रॉसिंग स्टेशन हैं। चार भारतीय पूर्वोत्तर राज्य - त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम - बांग्लादेश के साथ 1,880 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, जबकि मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं।

202 की दूसरी छमाही में 5जी लॉन्च की तैयारी के संकेत

नई दिल्ली।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने मंगलवार को वर्युअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) को संबोधित करते हुए उन 30 करोड़ भारतीयों की दशा पर चिंता जताई जो डिजिटल वर्ल्ड में आज भी 2जी तकनीक में फसे हैं। मुकेश अंबानी ने सरकार से आग्रह किया कि वह इस दिशा में कदम उठाए ताकि यह 30 करोड़ लोग भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सकें। मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्होंने 2जी से 30 करोड़ भारतीयों को मुक्त करने और उन्हें स्मार्टफोन पर शिफ्ट करने के लिए सरकार से पॉलिसी बनाने का अनुरोध किया। मुकेश अंबानी ने 2021 के दूसरी छमाही में स्वदेशी 5जी तकनीक लॉन्च करने की तैयारी के भी संकेत दिए। उन्होंने रिलायंस जियो की 5जी तकनीक को स्वदेशी बताया। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो की स्वदेशी 5जी तकनीक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत मिशन की सफलता का गवाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल मिशन की प्रशंसा करते हुए मुकेश अंबानी ने कोविड काल में इसे देश की डिजिटल लाइफ लाइन बताया। सरकार के प्रयासों की सरहना करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि देश जल्द ही सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर में भी अव्वल होगा। आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। दूरसंचार उद्योग के इस कार्यक्रम के चौथे संस्करण का आयोजन कोरोनावायरस महामारी के कारण पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये किया जा रहा है। कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर तक चलेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का विषय समग्र अन्वेषण - स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ है। इसके आयोजन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेश और निरंतर विकास, उद्यम तथा अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे तथा दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने कार्यक्रम में उपस्थित रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के अलावा भारतीय समूह के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारतीय मित्तल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 30 से अधिक देशों के 210 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पीकर और करीब 3,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। आईएमसी 2020 में विभिन्न मंत्रालयों, दूरसंचार कंपनियों के सीईओ, वैश्विक सीईओ, 5-जी तकनीक के एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर-सिक््योरिटी के एक्सपर्ट शिरकत करेंगे।



टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को टीके की मजबूरी नहीं

बीजिंग। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने 7 दिसंबर को आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों को एथल-19 का टीकाकरण करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2024 के Paris ओलंपिक खेलों के आधिकारिक खेल के रूप में ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, रॉक क्लाइंबिंग और सर्फिंग को मंजूरी दी। 7 दिसंबर को समाप्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की कार्यकारी समिति की बैठक के बाद आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में थॉमस बाख ने टोक्यो ओलंपिक और Paris ओलंपिक के उक्त नए फैसले बताए। उन्होंने कहा कि Covid-19 महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के कदम के हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक के ओलंपिक गांव के लिए एक संयुक्त गार्डलाइन बनायी। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों की मेजबानी की लागत और जटिलता को कम कर रही है। Paris ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या टोक्यो ओलंपिक से 592 कम होगी, और टीम के साथ जाने वाले अधिकारियों की संख्या भी कम हो जाएगी।



आईएसएल-7

चेन्नईयन से भिड़ेगा मुम्बई, टॉप पर बने रहने की होगी कोशिश



बोम्बोलिम (गोवा)।

मुम्बई सिटी एफसी बुधवार को बोम्बोलिम के जीएमसी स्टेडियम में दो बार के चैम्पियन चेन्नईयन

एफसी से भिड़ेगी और उसका मकसद यह मैच जीतते हुए हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के सातवें सीजन की अंक तालिका में टॉप स्पॉट बनाए रखना होगा।

हाईलैंड्स नाम से मराहूर नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी के हाथों अपने पहले मैच में मिली हार के बाद से स्पेनिश कोच सर्जियो लोबेरा की टीम ने स्टाइल में वापसी की और लगातार तीन मैच जीते। सोमवार को जमशेदपुर एफसी के हाथों एटीके मोहन बागान की 1-0 से हार का मतलब यह है कि मुम्बई टॉप पर बना हुआ है और अब उसे शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करने का अच्छा मौका मिल गया है। मुम्बई सिटी एफसी ने सीजन की शुरुआत में कई अहम करार किए थे और

अब उसे इसका फायदा मिलता दिख रहा है। मजबूत बेंच स्ट्रेंथ होने के कारण लोबेरा के पास खिलाड़ियों को रोटेट करने का मौका है। मुम्बई का डिफेंस काफी मजबूत दिख रहा है और इसका सबूत यह है कि मुम्बई ने अब तक सिर्फ एक गोल खाया है और तीन क्लीन शीट हासिल करने में सफल रहा है। इस अहम मैच से पहले लोबेरा ने कहा, हम मैच पर ध्यान बनाए हुए हैं। हम टेबल पर ध्यान नहीं देते क्योंकि यह गलती हो सकती है। हम जीतना चाहते हैं। हम टेबल में टॉप पर हैं और इस स्थिति से हम खुश हैं लेकिन हमारा असल मकसद अधिक से अधिक मैच जीतना है। यही हमारा लक्ष्य है। इस बीच, दो बार की चैम्पियन चेन्नईयन एफसी खुद को काफी टिकी सिचुएशन में पा रही है।

उसने जमशेदपुर पर 2-1 से जीत के साथ नए सीजन का आगाज किया था लेकिन उसके बाद दो मैचों में उसे जीत नहीं मिली। इन दो मैचों में वह गोल भी नहीं कर पाई। कोच साबा लाजलो का अटैक अच्छा है लेकिन वह मौकों को भुना पाने में नाकाम रही है। अब वह मुम्बई के खिलाफ जीत के साथ लय में लौटना चाहेगी। कोच ने मैच से पहले कहा, हम उनके (मुम्बई के) डिफेंस को अनलाक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम गोल करने में सक्षम हैं। हम अपनी मजबूती को जानते हैं। मुम्बई ने दिखाया है कि वह एक मजबूत टीम है लेकिन हम भी कमजोर नहीं हैं। हमारा खेल गोल करने की शैली का समर्थन करता है और अगले मैच में हम ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे।

जब तक पांड्या थे, जीत की उम्मीद थी : कोहली

सिडनी। आस्ट्रेलिया के हाथों मंगलवार को तीसरा और अंतिम टी-20 मैच हारने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि अगर 25-30 रन की और साझेदारी होती तो हार्दिक पांड्या मैच को निकाल सकते थे। कप्तान विराट कोहली (85) की शानदार अर्धशतकीय पारी के बावजूद भारत को मंगलवार को सिडनी क्रिकेट मैदान पर खेले गए तीसरे टी-20 मुकामबले में आस्ट्रेलिया के हाथों 12 रनों से हार मिली। भारत ने हालांकि इस हार के बावजूद तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कोहली ने मैच के बाद कहा, एक समय जब हार्दिक ने खेलना शुरू किया तो हमने सोचा कि हम इसे जीत सकते हैं। बीच के ओवरों में हमारी बल्लेबाजी सही नहीं रही। अगर 30 रन की और साझेदारी होती तो हार्दिक के लिए थोड़ा आसान होता। हम वापसी की राह पर थे। लेकिन सीरीज जीत के साथ 2020

सीजन की समाप्ति करना हमारे लिए थोड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि दर्शक एक कारण था और यह हमेशा आपको प्रेरणा देती है। दर्शकों के होने से कभी कभी हमें तो कभी-कभी आस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को ऊर्जा मिलती है। भारत को अब 17 अर्धशतकीय पारी के बावजूद भारत को मंगलवार को सिडनी क्रिकेट मैदान पर खेले गए तीसरे टी-20 मुकामबले में आस्ट्रेलिया के हाथों 12 रनों से हार मिली। भारत ने हालांकि इस हार के बावजूद तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कोहली ने मैच के बाद कहा, एक समय जब हार्दिक ने खेलना शुरू किया तो हमने सोचा कि हम इसे जीत सकते हैं। बीच के ओवरों में हमारी बल्लेबाजी सही नहीं रही। अगर 30 रन की और साझेदारी होती तो हार्दिक के लिए थोड़ा आसान होता। हम वापसी की राह पर थे। लेकिन सीरीज जीत के साथ 2020



जरूरत है। हमें इसे सत्र दर सत्र लेने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि मौजूदा टीम पिछली टीम (टेस्ट मैचों के लिए) से काफी मजबूत है।

संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार देगी सरकार, पूरे देश में खोले जाएंगे खेलो इंडिया केंद्र

नई दिल्ली। खेल मंत्री किरन रिजजू ने मंगलवार को कहा कि सरकार संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेंगी। रिजजू ने फिक्की के 10वें वार्षिक खेल सम्मेलन टर्फ 2020 के दौरान कहा, 'हम देश भर में 1000 खेलो इंडिया लघु केंद्रों को भी शुरू करने जा रहे हैं जिससे संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार हासिल करने या देश में खेल संस्कृति के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो इससे भावी पीढ़ियां हतोत्साहित होती हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि खिलाड़ियों और लाभार्थी के पास बिना किसी रुकावट के सरकार से मिलने वाली पुरस्कार राशि, वित्तीय सहयोग पहुंचे। रिजजू ने इस अवसर पर कारपोरेट घरानों से देश में खेल प्रेमी समाज के निर्माण में मदद करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा, 'सरकारी समर्थन की कोई कमी नहीं है लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है जिसे खेलों के लिए जाना जाता हो। सरकारी प्रयास कभी पर्याप्त नहीं होते। लोगों के प्रयास, लोगो की भागीदारी से खेलों में सफलता मिलेगी। इस समारोह में ओलंपिक रजत पदक विजेता पी वी सिंधु, मध्यप्रदेश की खेल मंत्री सुशोभा राजे सिंधिया, आस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति के सीईओ मैट कैरोल और फिक्की अध्यक्ष डा. संगीता रेड्डी आदि ने भी भाग लिया।



सिडनी टी-20 ~ कोहली के 85 रनों के बावजूद भारत हारा, सीरीज अपने नाम की

सिडनी।

कप्तान विराट कोहली (85) की शानदार अर्धशतकीय पारी के बावजूद भारत को मंगलवार को सिडनी क्रिकेट मैदान पर खेले गए तीसरे टी-20 मुकामबले में आस्ट्रेलिया के हाथों 12 रनों से हार मिली। भारत ने हालांकि इस हार के बावजूद तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। भारत को जीत के लिए 187 रनों का लक्ष्य मिला था लेकिन वह कप्तान की शानदार पारी के बावजूद निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 174 रन ही बना सके। इसका कारण यह रहा कि भारत की ओर सिर्फ कोहली ही चल सके। शिखर धवन ने 28 रन बनाते हुए कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी की थी जबकि हार्दिक पांड्या (20) ने पांचवें विकेट के लिए 44 रनों की साझेदारी की। कोहली ने अपनी 61 गेंदों की पारी में चार चौके और तीन छक्के लगाए। अंत में शार्दूल ठाकुर ने सात गेंदों पर दो छक्कों की मदद से नाबाद 17 रन बनाकर भारत को नया पार



लाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसने पारी की दूसरी ही गेंद पर लोकेश राहुल (0) को खो दिया। इसके बाद शिखर धवन (28) ने कप्तान विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी की। धवन 21 गेंदों का सामना करने के बाद मिशेल स्कॉट की गेंद पर डेनियल सैमस के हाथों कैच हुए। संजू सैमसन (10) भी अधिक देर

नहीं चल सके। सैमसन को भी स्वीपसन ने स्टीवन स्मिथ के हाथों कैच करवाया। सैमसन ने नौ गेंदों का सामना किया। सैमसन का विकेट 97 के कुल योग पर गिरा। यह विकेट 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर गिरा था और इसी ओवर की छठी गेंद पर स्वीपसन ने श्रेयस अय्यर (0) को पगबाधा आउट कर भारत को चौथा झटका दिया। अय्यर का विकेट 100 के कुल योग पर गिरा।

पुकोवस्की के सिर में लगी गेंद, दूसरे अभ्यास मैच से बाहर

सिडनी। आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज विल पुकोवस्की को इंडिया-ए के खिलाफ खेले गए पहले अभ्यास मैच के तीसरे और अंतिम दिन सिर में गेंद लग गई और फिर इसके बाद वह कनकशन का शिकार हो गए। पुकोवस्की का 17 दिसंबर से भारत के खिलाफ शुरू होने वाली चार मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में खेलना तय माना जा रहा है। इस मैच से वह टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने को तैयार हैं। पुकोवस्की को आस्ट्रेलिया-ए की पारी के 13वें ओवर के दौरान हेलमेट पर इंडिया-ए के तेज गेंदबाज कार्लिंक त्यागी का बाउंडर लगा और फिर वह सीधे जमीन पर गिर गए और रिटावर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम लौट गए। आस्ट्रेलियाई मीडिया में जारी खबरों के अनुसार, पुकोवस्की की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन वह शुरुवार से शुरू होने वाले दूसरे अभ्यास मैच से बाहर हो गए हैं। टीम डॉक्टर जान ओर्चाई ने कहा, 'विल में कनकशन के हल्के लक्षण हैं लेकिन वह खुद बिना किसी सहायता के मैदान के बाहर गया। उन्होंने कहा, हमारे मेडिकल रूम में उनकी देखभाल की गई। वह स्टाफ, टीम के साथियों और फोन पर परिवार से आराम से बात कर रहे थे। वह आस्ट्रेलिया-ए टीम के साथ रहेंगे, लेकिन दूसरा अभ्यास मैच नहीं खेलेंगे। 22 साल पुकोवस्की ने जूड़ा हुए पहले मैच में एक और 23 रन बनाए थे। वह इससे पहले भी अपने करियर में कनकशन चोट का शिकार हो चुके हैं। वह अब तक सात या आठ बार चोटिल हो चुके हैं।



बीबीएल : बैश बूट नियम से स्पॉट फिटिंग के खतरों से सीए सतर्क

सिडनी। क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) 10 दिसंबर से शुरू रहे ही बिग बैश लीग (बीबीएल) के 10वें संस्करण में बैश बूट नियम लागू करने जा रही है और उससे पहले ही वह कमेंटरी और खिलाड़ियों को मैदान पर बातचीत नहीं करने की चेतावनी देगा। सीए ने पिछले महीने ही पावरसर्ज, एक्सप्लोडर और बैश बूट के रूप में तीन नए नियम को पेश किया है, जोकि बीबीएल के 10वें संस्करण में लागू होगा। बैश बूट बोनस अंक है जो दूसरी पारी के बीच में दिए जाएंगे। दूसरी पारी खेलने वाली टीम अगर 10 ओवर के बाद पहली पारी खेल चुकी टीम के 10 ओवर के स्कोर से ज्यादा बना लेगी तो उसे यह बोनस अंक दिया जाएगा, लेकिन नहीं बना पाती है तो फील्डिंग टीम को यह अंक दिया जाएगा। द ऐज की रिपोर्ट के अनुसार, सीए प्रसारणकर्ता सेवन वेस्ट मीडिया और फॉक्स क्रिकेट के कमेंटरी के साथ काम करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 10वें ओवर दौरान और सट्टे बाजारों को दूर रख सके। हालांकि आईसीसी से पूर्व मुख्य कार्यकारी और भ्रष्टाचार विरोधी विशेषज्ञ मैल्कम स्पीड का मानना है कि बीबीएल के इस कदम से स्पॉट फिटिंग को बढ़ावा मिलेगा। स्पीड ने कहा, यह खेल के कई पहलुओं में से एक है जिस पर सट्टा लगाया जा सकता है लेकिन यह थोड़ा अलग होगा। अगर कोई फिक्सर कुछ करना चाहता है तो इसे इसके माध्यम से करने का यह आसान तरीका है। उन्होंने कहा, मैं इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हूँ। अगर आप एक अनोखा फिल्ड रखना चाहते हैं, तो आप आठवां, 10 वां और 12वां ओवर चुन सकते हैं। अगर आपको इसमें फिक्सर मिलता है, तो यह एक अच्छा मौका है। मुझे नहीं लगता कि यह पहले से जो कुछ अलग है। पावर सर्ज नियम में, फील्डिंग टीम सर्कल के बाहर सिर्फ दो खिलाड़ी ही रख सकेगी। बल्लेबाजी करने वाली टीम 11वें ओवर से अपनी पारी में कभी भी इस नियम का इस्तेमाल कर सकेगी।

महिला हॉकी : उदिता ने कहा, हमारा ध्यान टोक्यो ओलंपिक पर

बेंगलुरु।

भारतीय महिला हॉकी टीम के अर्टकम मिडफील्डर उदिता ने अगले साल टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और उनका मानना है कि अगले सात महीने उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदिता ने कहा, मुझे एशियाई खेलों और लंदन में हुए विश्व कप जैसे कुछ बड़े आयोजनों में भारत के लिए खेलने का मौका मिला है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जहां हमने टीम के रूप में कुछ महत्वपूर्ण प्रदर्शन किए। हिसार, हरियाणा की नौजवान खिलाड़ी ने टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने को लेकर

कहा, अब, पूरी टीम का केवल एक फोकस है और वह टोक्यो में होने वाला ओलंपिक खेल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले सात महीने हमारे जीवन और हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। उदिता ने पहली बार राष्ट्रीय परिदृश्य में घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद 2015 में प्रवेश किया। उन्हें जूनियर राष्ट्रीय शिबिर के लिए चुना गया था। 2016 में जूनियर इंडिया टीम के लिए



पदार्पण करने के बाद, उन्होंने 2016 में चौथे यू-18 महिला एशिया कप में कांस्य जीतने वाली जूनियर इंडिया टीम की कप्तानी की थी। 2017 में, उन्होंने सीनियर टीम के लिए पदार्पण किया।

ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ ब्रेकडांस, युवा दर्शकों को लुभाने के लिए लिया फैसला

जिनेवा। ब्रेकडांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए आईओसी ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी इन खेलों में शामिल किया गया है। इन तीन खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था जो कोरोना वायरस महामारी के कारण एक साल के लिए स्थगित कर दिए गए। आईओसी ने पेरिस खेलों में पदक स्पर्धाओं की संख्या टोक्यो की तुलना में दस कम कर दी यानी अब वहां 329 पदक स्पर्धाएं होंगी। भारोत्तोलन की चार श्रेणियां कम कर दी गई हैं। इसके साथ ही 2024 में खिलाड़ियों का कोटा 10500 होगा जो टोक्यो ओलंपिक से 600 कम है। प्रशासनिक अनियमितताओं को झेल रहे मुम्बईवासी और भारोत्तोलन से सबसे ज्यादा कटौती की गई है। पेरिस खेलों में भारोत्तोलन में 120 खिलाड़ी होंगे जो रियो दि जिनिरियो की तुलना में आधे से भी कम है। डोपिंग के इतिहास और सुधार लागू करने की धीमी गति के कारण इसे पूरा भी हटया जा सकता था। आईओसी ने यह भी कहा कि ओलंपिक में उसका दीर्घकालिन लक्ष्य पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान भागीदारी है।

क्रिकेट्स आगे आए तो सद्दा या जुआ ऐप की बदनाम छाया से निकले फेटेसी ऐप्स

नई दिल्ली।

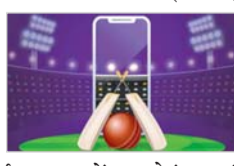
फेटेसी स्पोर्ट्स उद्योग की लड़ाई जारी भी उस गलत धारणा से जारी है जो इसे जुए या स्पोर्ट्स बेटिंग के समान मानती है। फेटेसी स्पोर्ट्स ऐप को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट की दुनिया के अनेकों खिलाड़ी हाल ही में जांच के घेर में आ चुके हैं, क्योंकि इन ऐप्स को अक्सर सट्टे या जुए का ऐप मान लिया जाता है। लेकिन, क्या ऐसे गेम का विज्ञापन करने के लिए ब्रांड एंबेसडर्स पर सवाल उठाना जा सकता है जिन्हें अदालतों, सरकारों और विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों

द्वारा कौशलपूर्ण खेल के तौर पर समर्थन मिल चुका है? भारत की प्रमुख ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्स ट्वेंटी फोर सेक्टर के सह सस्थापक एवं सीईओ भाविन पंड्या ने इसे लेकर आईएनएस से बात की। पंड्या ने कहा कि, फेटेसी स्पोर्ट्स जुआ उत्पादों से बहुत अलग हैं क्योंकि इसमें प्रतियोगिता पारदर्शी होती है। तकनीक और डेटा की उपलब्धता से खिलाड़ियों को शानदार कौशल दिखाकर एवं सजगता बरतते हुए खेल कार्यक्रम में असल जिंदगी के खिलाड़ियों के आधार पर उनकी खुद की टीम बनाने में मदद

मिलती है। इसलिए, फेटेसी स्पोर्ट्स के व्यवसाय से जुड़ा कोई भी क्रिकेटर या सेलेब्रिटी एक बेहद कानूनी ढंग से ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय का समर्थन कर रहा है। भारत में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित कई उच्च न्यायालयों ने खेल की वैधता का परीक्षण किया है और इसे महज कुशलता के एक खेल के तौर पर करार दिया है। फेटेसी स्पोर्ट्स उद्योग ने धुआंधार गति से वृद्धि की है। आज इसके 20 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता और लगभग 200 कंपनियां हैं। परामर्शी संगठन, के पीएमजी को उम्मीद है कि

2024 के अंत तक यह उद्योग 3.7 अरब डॉलर का हो जाएगा। पंड्या मानते हैं कि क्रिकेट्स द्वारा इसे प्रोमोट किए जाने से एक बेहतर खेल इकोसिस्टम बनाने में मदद मिली है। पंड्या ने कहा, बीसीसीआई ने मार्च 2019 में आधिकारिक आइवीएल पार्टनर के तौर पर एक फेटेसी स्पोर्ट्स ऑपरेटर को शामिल किया, जिससे इस सेक्टर को काफी बल मिला। तब से एमएस धोनी, विराट कोहली, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, विरेन्द्र सहवाग, इफान

पठान, के.एल. राहुल, और रोहित शर्मा जैसे कई क्रिकेटर्स ने फेटेसी स्पोर्ट्स ब्रांड्स का विज्ञापन किया और क्रिकेट फैंस से जुड़ाव बनाया। इससे जुआ उद्यम की जगह एक स्वस्थ खेल मनोरंजन परितंत्र का निर्माण हो रहा है। हालांकि अमेरिका में फेटेसी स्पोर्ट्स को बेसबॉल के खेल की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, लेकिन 2019 तक 5 करोड़ खेल प्रेमी पहले से ही फेटेसी ऐप्स पर खेल रहे थे।



दुग्ध कारोबार में रोजगार के मौके

प्रशिक्षण संस्थान

- नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल
- इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (इग्नू) नई दिल्ली
- आणंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आणंद
- इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद

भारत का नाम दुनिया के बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में शामिल है। पूरे विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत में करीब 12-15 फीसदी उत्पादन भारत में ही होता है। जानकारों का कहना है कि यदि विकास दर यही रही तो अगले कुछ सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 30-35 फीसदी तक पहुंच जाएगी। दुग्ध कारोबार के बढ़ने से स्वाभाविक है कि रोजगार के मौके भी खूब बढ़ेंगे।



डेयरी टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर कई तरह के कोर्स संचालित होते हैं, जो मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों डेयरी इंजीनियरिंग, डेयरी केमिस्ट्री तथा डेयरी बैक्टीरियोलॉजी से संबंधित हैं। कोर्स के दौरान छात्रों को मिल्क प्रोडक्शन, डेयरी इक्विपमेंट एंड यूटीलिटीज, मिल्क प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, इश्योरेंस, डेयरी मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग से संबंधित जानकारीयों दी जाती हैं। वर्तमान समय में जो भी कोर्स संचालित हो रहे हैं, उनमें दखिला पाने के लिए छात्रों को साइंस स्ट्रीम से 12वीं कक्षा 50 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी इन पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर सकते हैं। संबंधित ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट में बारहवीं स्तर के भौतिकी, रसायन,

गणित, कृषि एवं एनिमल साइंस से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। नेटरिनरी कॉन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा 'ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस एग्जाम' तथा इंडियन कार्सिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा 'ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम' कराया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बीपीपी (बैचलर प्रिपेटरी प्रोग्राम) कोर्स करवाता है। दुग्ध उत्पादों से जुड़ी कंपनियों में हर वर्ष रिक्तियां निकलती रहती हैं। देश में अनेक डेयरी फाउंडेशन तथा प्लांट हैं, जिनके यहां प्रोफेशनलों की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त डेयरी फेडरेशन, को-ऑपरेटिव स्ल बैक, मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, स्ल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े विभाग, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आदि में हर वर्ष इससे संबंधित प्रोफेशनलों की मांग होती है। इसके अलावा नेशनल डेयरी

डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) व प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जैसी कई संस्थाएं हैं, जो लोगों को गांवों में जाकर प्रशिक्षण देने के साथ-साथ जगह-जगह अपना बूथ लगा रही हैं तथा स्थानीय लोगों को काम भी दे रही हैं। डेयरी इंडस्ट्री में स्वरोजगार शुरू करने से पहले यदि एंटरप्रायोरिप कोर्स कर लिया जाए तो कई आधारभूत चीजों जैसे बिजनेस की बारीकियां, डेयरी उद्योग कैसे लगाएं, कॉमर्शियल ट्रेनिंग फार्मिंग, लोन आदि की जानकारी हो जाती है। एनडीआरआई जैसे कई संस्थान इस तरह के कोर्स चलाते हैं। इन्हीं शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए कई तरह के टेक्निकल सपोर्ट भी उद्यमी को मिलते हैं। विजिटिंग फेकल्टी के रूप में बैक, नाबार्ड व बिजनेस इंडस्ट्री वालों की मदद ली जाती है। यदि कोई खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो डेयरी फार्म या बूथ खोलने के लिए नाबार्ड, को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन सहित कई बैंक उद्यमियों को लोन भी प्रदान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग स्क्रीम होती हैं। प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा त+ण प्रदान किया जाता है, वहीं नाबार्ड के जरिए भी लोन जिला प्रबंधक, नाबार्ड की मदद से प्राप्त किया जा सकता है।

फॉरेंसिक में फलत फूलता करियर

इतिहास : छुपा है बेहतरीन करियर

नाकामी ही बनाती है कामयाब



फॉरेंसिक साइंस, साइंस तो है लेकिन इसे केवल साइंस का ही पार्ट नहीं मान सकते हैं। केवल साइंस के स्टूडेंट ही इसकी पढ़ाई करें, ऐसी भी बाध्यता नहीं है। साइंस के स्टूडेंट को इसे समझने में ज्यादा सहूलियत होती है। फॉरेंसिक साइंस अब विदेश में ही नहीं, देश में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस क्षेत्र में नौकरियों की भरमार को देखते हुए स्टूडेंट्स का तेजी से इस ओर तेजी से ख्यान हो रहा है। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने वाले के लिए पढ़ाई के तमाम ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो डिप्लोमा कोर्स करें या फिर पीएचडी। अच्छी बात तो यह है कि हर स्तर पर नौकरी का स्कोप है। डिप्लोमा कोर्स करने के भी आप करियर शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आगे की पढ़ाई करते जाएं और करियर को बढ़ाते जाएं। फॉरेंसिक साइंस बेसिक रूप से अपराध से जुड़ा विज्ञान है और इसका इस्तेमाल भी सबसे अधिक अपराध का पता लगाने के क्षेत्र में ही होता है। आने वाले दिनों में इसकी मांग बढ़ने के आसार हैं। अपराधियों का पता लगाने के लिए खून, थूक समेत शरीर के अन्य तरल पदार्थ की जांच की जाती है। अदालत भी फॉरेंसिक रिपोर्ट को अहम गवाह मानती है।

फॉरेंसिक साइंस का ही पार्ट नहीं मान सकते हैं। केवल साइंस के स्टूडेंट ही इसकी पढ़ाई करें, ऐसी भी बाध्यता नहीं है। हां साइंस के स्टूडेंट को इसे समझने में ज्यादा सहूलियत होती है। फॉरेंसिक साइंस अब विदेश में ही नहीं, देश में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। इस क्षेत्र में नौकरियों की भरमार को देखते हुए स्टूडेंट्स का तेजी से इस ओर तेजी से ख्यान हो रहा है। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने वाले के लिए पढ़ाई के तमाम ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो डिप्लोमा कोर्स करें या फिर पीएचडी। अच्छी बात तो यह है कि हर स्तर पर नौकरी का स्कोप है। डिप्लोमा कोर्स करने के भी आप करियर शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आगे की पढ़ाई करते जाएं और करियर को बढ़ाते जाएं। फॉरेंसिक साइंस बेसिक रूप से अपराध से जुड़ा विज्ञान है और इसका इस्तेमाल भी सबसे अधिक अपराध का पता लगाने के क्षेत्र में ही होता है। आने वाले दिनों में इसकी मांग बढ़ने के आसार हैं। अपराधियों का पता लगाने के लिए खून, थूक समेत शरीर के अन्य तरल पदार्थ की जांच की जाती है। अदालत भी फॉरेंसिक रिपोर्ट को अहम गवाह मानती है।

इतिहास जैसे विषय के बारे में सामान्य तौर पर यही धारणा है कि परीक्षाओं में एक विषय के रूप में इसे लिया जा सकता है, परंतु इसके माध्यम से करियर बनाया जा सकता है, इस बारे में काफी कम ही विचार होता है। इतिहास को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही पढ़ा जाता है और आईएस और पीएससी जैसी परीक्षाओं के दौरान इन विषयों का गहन अध्ययन होता है। किसी देश की सभ्यता और संस्कृति जानने के लिए इतिहास पढ़ना बेहद जरूरी है। इतिहास विषय के साथ स्नातक करने के बाद हैरिटेज मैनेजमेंट का कोर्स भी किया जा सकता है, क्योंकि आज भारत में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण, खुदाई और शोध के काम पर काफी जोर दिया जा रहा है।

इस दिशा में पुरातत्व विभाग की सक्रियता इतिहास के छात्रों के लिए करियर के नए अवसर प्रदान कर रही हैं। पर्यटन के क्षेत्र में इन्फर्मेशन मैनेजर का अहम योगदान होता है। आने वाले समय में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में उभरकर सामने आएगा। इन दिनों पर्यटन उद्योग का विस्तार पूरे देश में हो रहा है। यदि इन्फर्मेशन मैनेजर को इतिहास की अच्छी जानकारी है, तो किसी भी देश में आने वाले टूरिस्ट को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर कार्य हो रहा है, ऐसे में अगर युवा साथी अपने ही राज्य के ऐतिहासिक स्मारकों व अन्य जानकारीयों को आत्मसात करें व साथ में इतिहास की अच्छी डिग्री उनके पास हो, तब पर्यटन के क्षेत्र में बढ़िया करियर बनाया जा सकता है।

कामयाब लोगों की जिंदगी हमेशा असफलता से शुरू होती है, इसके एक नहीं कई एग्जाम्पल्स इतिहास में देखे जा सकते हैं। अमेरिका के पहले अरबपति जॉन डी. रॉकफेलर सीनियर, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड, विश्वप्रसिद्ध कंप्यूटर कंपनी डेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल डेल, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जैसे सैकड़ों-हजारों सफल व्यक्तियों ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि कभी हासिल नहीं की।

इनमें से कई तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाए और कई को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। आगे चलकर यही लोग स्कूल-कॉलेजों में स्कॉलरशिप बांटने और डॉक्टरेट की उपाधियां पाने लगे। यानी जीवन में पढ़ाई-लिखाई जरूरी तो है पर अगर मन में विश्वास है तो उसके बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जल्द ही बस अपने अंदर छिपी प्रतिभा को जानने और उस पर अमल करने की।

न्यूटन, आईस्टीन, सचिन तेंडुलकर, पेंले, मोहम्मद अली आदि हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी असफल जख्र हुए हैं। आम आदमी और इनमें सिर्फ यही अंतर रहा कि इन्होंने असफलताओं से सीख लेकर उसी को सफलता की सीढ़ी बना लिया। एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुँचने वाले पहले इंसान थे, लेकिन वे भी एक बार के प्रयास में ही सफल नहीं हो गए थे। उन्होंने 1952 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की, पर असफल रहे। इस अभियान के कुछ हफ्ते बाद जब एक कार्यक्रम में उनसे कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट की एक तस्वीर की ओर रख करके जोशिले अंदाज में मुक्का ताना और कहा, तुमने मुझे पहली बार तो हरा दिया माउंट एवरेस्ट, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें हराऊंगा, क्योंकि तुम तो बढ नहीं सकती, पर मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अगले वर्ष 29 मई, 1953 को एडमंड हिलेरी ने यह कर भी दिखाया।

कम शिक्षा में जॉब

उच्च शिक्षा वालों के लिए तो तमाम अवसर उपलब्ध हैं ही, यदि आप कम शिक्षित हैं या दसवीं पास हैं, तो भी कैरियर के कई ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध हैं...

आईटीआई में सर्टिफिकेट कोर्स

सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता है कि कैरियर में अच्छा करने के लिए कम-से-कम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। यह सच भी है, पर ऐसा नहीं है कि किसी कारणवश यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। यहां तक कि जो अभ्यर्थी दसवीं पास या उससे भी कम शिक्षित हैं, उनके लिए भी तमाम मौके उपलब्ध हैं। एक बात और, कम शिक्षित होने के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का मतलब यह कदाई नहीं है कि आपके लिए सीमाएं बंध गईं। अपनी वर्तमान शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कोई नौकरी प्राप्त करने के बाद आप चाहें तो उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक फायदा यह भी होगा कि आपको काम का भी अनुभव हो जाएगा।

डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 12वीं (पीसीएम) के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश या तो 10वीं-12वीं के अंकों के आधार पर मिलता है या एंट्रेंस टेस्ट चयन का आधार बनता है। सरकारी संस्थानों के अलावा निजी संस्थान भी हैं, जिसमें 50 प्रतिशत सीटों के लिए फीस नाममात्र की ली जाती है। पॉलिटेक्नीक संस्थान राज्य के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से संबद्ध होते हैं और इन्हें एआईसीटीई से भी मान्यता प्राप्त होती है।

डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 12वीं (पीसीएम) के विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश या तो 10वीं-12वीं के अंकों के आधार पर मिलता है या एंट्रेंस टेस्ट चयन का आधार बनता है। सरकारी संस्थानों के अलावा निजी संस्थान भी हैं, जिसमें 50 प्रतिशत सीटों के लिए फीस नाममात्र की ली जाती है। पॉलिटेक्नीक संस्थान राज्य के बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से संबद्ध होते हैं और इन्हें एआईसीटीई से भी मान्यता प्राप्त होती है।

डिस्टेंस एजुकेशन से फायदा वैसे भी प्रोफेशनल कोर्सेज के इस जमाने में जनरल स्टडी में तीन-चार साल गंवाने के बजाय कोई जॉब पकड़ लेना और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा या जॉब ओरियन्टेड डिग्री प्राप्त करके कैरियर को नई दिशा देना बुद्धिमाना भरा कदम है। कम शिक्षित युवाओं के लिए एआईटीआई, पॉलिटेक्नीक, पैरामेडिकल, कंप्यूटर, टूरिज्म तथा अन्य प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगते हैं।

सेना में मौके

भारतीय सेना में भी 10वीं पास अभ्यर्थियों को मौके मिलते हैं, यदि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड को पूरा करते हैं। जनरल ड्यूटी के तहत सोल्जर (आयु साइज 17 से 21 वर्ष) के रूप में नियुक्ति के लिए मैट्रिक 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा सोल्जर ट्रेड्समैन के रूप में भी 10वीं पास वैसे अभ्यर्थी नियुक्ति पा सकते हैं, जिनके पास आईटीआई का भी संबंधित डिप्लोमा है। मेस कोपर व हाउस कोपर के रूप में तो 8वीं पास छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में भी वैसे विद्यार्थियों को भी मौके मिल सकते हैं, जो नन-मैट्रिक हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को यूजिशियन, स्पोट्स



फॉरेंसिक साइंस के कोर्स

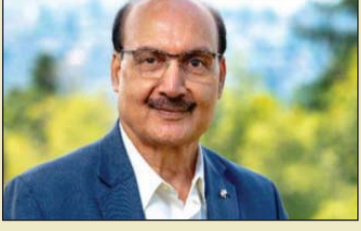
- पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक स्पीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी
 - पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस
 - पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्रिमिनॉलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस
 - पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग
 - मास्टर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस
 - मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर फॉरेंसिक एंड इन्फोमेशन सिक्युरिटी
 - सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रांड डिटेक्शन
 - बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेंसिक साइंस
- कहां से करें कोर्स**
निम्न संस्थानों से फॉरेंसिक साइंस में बीएससी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स किए जा सकते हैं।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनॉलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, नई दिल्ली
 - इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, मुंबई
 - यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, चेन्नई
 - ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हीयरिंग, मैसूर

पॉलिटेक्नीक कोर्स

विभिन्न पॉलिटेक्नीक संस्थानों द्वारा डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। डिप्लोमा कोर्स 2 से 4 साल की अवधि का हो सकता है। इसमें मैट्रिकुलेशन 10वीं पास अभ्यर्थी प्रवेश पा सकते हैं, जबकि

सार समाचार

भारत के लिए गौरवशाली पल! ब्रिटिश कोलंबिया के स्पीकर चुने गए राज चौहान



टोरंटो। कनाडा में भारतीय मूल के विधायक राज चौहान को ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं। वह समुदाय के पहले नेता हैं, जो इस पद पर काबिज हुए हैं। यह जानकारी मीडिया की खबरों में दी गई है। कनाडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (सीबीसी) न्यूज ने सोमवार को खबर दी कि ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा में चौहान ने बर्नबी-एडमंड्स क्षेत्र का पांच बार प्रतिनिधित्व किया है और पिछली सरकार में वह उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष के तौर पर वह डेरिल फ्लेकास का स्थान लेगे।

पंजाब में जन्मे चौहान 1973 में कनाडा चले गए और खेत में काम करने लगे। अन्य प्रवासी मजदूरों के शोषण और धनी देश में गरीबी और धनी के बीच भेद का उन पर काफी प्रभाव हुआ। खबर में बताया गया कि समुदाय और कामगारों के सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने काफी योगदान दिया। खबर में चौहान के हवाले से बताया गया, "विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा यह भूमिका देने के लिए मैं वास्तव में उनका आभारी हूँ।"

ईरान के इस पत्रकार की मौत की सजा बरकरार, जासूसी के मामले में सुनाई गई सजा



तेहरान। ईरान के उच्चतम न्यायालय ने तीन साल पहले देश में विरोध प्रदर्शन के लिए लोगों को भड़काने के जुर्म में एक पत्रकार को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। ईरान की अदालत 'तसनीम समाचार एजेंसी' के मंगलवार को न्यायापालिका के प्रवक्ता गोलमहोससीन इस्माइली के हवाले से बताया है कि उच्चतम न्यायालय ने रुहुल जम को सुनाई गई मौत की सजा को बरकरार रखा है। यह पता नहीं चल पाया है कि पत्रकार को कब सजा सुनायी गयी। इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि जम को कब सजा दी जाएगी। ईरानी कानून के तहत जम के पास सजा के खिलाफ अपील करने का मौका है और न्यायापालिका प्रमुख के पास सजा पर रोक लगाने का अधिकार है। जून में एक अदालत ने जम को मौत की सजा सुनायी थी। उन्हें जासूसी, ईरानी सरकार को बेदखल करने के प्रयासों के जुर्म में सजा सुनायी गयी। आरोप लगाया गया कि जम की वेबसाइट और मैसेंजिंग ऐप टेलीग्राम पर एक चैनल के जरिए प्रदर्शन के बारे में सूचनाएं दी जाती थी।

उत्तरी आयरलैंड की 90 वर्षीय महिला को लगा फाइजर का पहला टीका

लंदन। उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की एक महिला कोविड-19 से बचाव के लिए फाइजर/बायोन्टेक द्वारा निर्मित टीका लगवाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। मार्गरेट कीनान को टीका लगाए जाने के साथ ही ब्रिटेन के सामूहिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई। एमिस्कलेन की रहने वाली कीनान ने टीका लगवाने के बाद कहा कि उन्हें "बहुत खास" महसूस हो रहा है। उन्हें कोविड-19 के एंटीबॉडी हॉस्पिटल में टीका लगाया गया है। बीबीसी की खबर के मुताबिक कीनान दुनिया की ऐसी पहली व्यक्ति हैं जिन्हें ट्रायल से तैयार फाइजर/बायोन्टेक कोविड-19 का टीका लगाया गया। ब्रिटेन की 'दवा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन नियामक एजेंसी' (एमएचआरए) ने पिछले हफ्ते इस टीके को मंजूर दी।

ब्रिटेन में पहले भारतवंशी शख्स को दी जाएगी कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक

लंदन। उत्तर-पूर्वी इंग्लैंड के भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरि शुक्ला दुनिया के उन कुछ पहले लोगों में शामिल होंगे, जिन्हें कोविड-19 का टीका लगाया। शुक्ला को न्यूकैसल में एक अस्पताल में 'फाइजर/बायोन्टेक' द्वारा विकसित टीका लगाया जाएगा। टाइन एंड वेयर के निवासी शुक्ला ने कहा कि उन्हें लगता है कि अपने टीके की पहली दो खुराक लगवाना उनका कर्तव्य है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस पल को "एक बड़ी प्रगति" बताया और ब्रिटेन में मंगलवार को "वी-डे" या "वेक्सीन डे" होने की बात कही। शुक्ला ने कहा, "मैं बहुत खुश हूँ कि अंततः हम इस वैश्विक महामारी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और मैं खुश हूँ कि टीका लगावा कर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह मेरा कर्तव्य है और मदद के लिए जो हो सकेगा वह मैं करूंगा।" उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) के साथ लगातार सम्पर्क में रहने की वजह से, मुझे पता है कि उन सभी ने कितनी मेहनत की है और उन सभी के लिए बड़ा सम्मान है... उनका दिल बहुत बड़ा है और वैश्विक महामारी के दौरान हमें सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ।"

ब्रिटेन-यूरोपीय संघ वार्ता टूटने के कगार पर पहुंची, जॉनसन की ब्रसेल्स यात्रा असंभव?

लंदन। (एजेंसी)।

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) ने मंगलवार को चेतावनी दी कि ब्रेक्सिट बाद के मुक्त व्यापार समझौते पर उनके बीच वार्ता टूटने के कगार पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के, यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन के साथ आमने-सामने की वार्ता को कोई सफलता मिलने की संभावना को तबज्जो नहीं दिया है। महीनों की तनावपूर्ण वार्ता के बाद अहम मुद्दों पर वार्ताकारों के बीच गतिरोध कायम है। इस बीच जर्मन यूरोपीय मामलों के मंत्री माइकल रोथ ने कहा कि ब्रिटेन पर ईयू का विश्वास अधर में लटक रहा है। उन्होंने कहा, "हमें लंदन में राजनीतिक इच्छा

शक्ति की जरूरत है।" रोथ के देश जर्मनी के पास अभी ईयू की अध्यक्षता है, जो चक्रीय आधार पर दी जाती है। उन्होंने कहा, "एक बात में स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हमारे भविष्य के संबंध विश्वास एवं भरोसे पर आधारित हैं।"

यह विश्वास अभी हमारी वार्ता में खासतौर पर दांव पर लगा हुआ है।" रोथ ने ईयू के अपने समकक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस वार्ता की अध्यक्षता करने से पहले कहा, "हम एक समझौते पर पहुंचना चाहते हैं लेकिन कोई कीमत चुकाने हुए नहीं।" वहीं, जॉनसन के कार्यालय ने कहा है कि स्थिति बहुत नाजुक है और वार्ता के टूटने की पूरी संभावना है। जॉनसन और लेयेन ने 48 घंटे में दूसरी बार

सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कितीन अहम मुद्दों--मछली पकड़ने के अधिकार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नियम और भविष्य के विवादों के निपटारे-- पर मतभेद कायम है।

दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि आगामी दिनों में ब्रसेल्स में एक-दूसरे के साथ बैठक कर शेष मतभेदों पर चर्चा करने की उनकी योजना है। ईयू के 27 सदस्य देशों के नेता ब्रसेल्स में दो दिवसीय बैठक कर रहे हैं जो बहुसंख्यक से शुरू हो रही है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन 31 जनवरी को ईयू से राजनीतिक रूप से बाहर हो गया था लेकिन वह इस संगठन के प्रशुल्क मुक्त एकल बाजार और कस्टम यूनिन में 31 दिसंबर तक मौजूद है।



पाकिस्तान, चीन और म्यांमार समेत इन देशों में नहीं है धार्मिक स्वतंत्रता! अमेरिका ने जारी की सूची

वॉशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन को उन देशों की सूची में शामिल किया है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन विशेष चिंता का विषय है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह जानकारी दी। पोम्पियो ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और चीन के अलावा म्यांमार, इरिट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को उस सूची में रखा गया है जो "धार्मिक स्वतंत्रता के व्यवस्थित, निरंतर एवं घोर उल्लंघन" में लिप्त हैं या फिर ये उल्लंघन होने दे रहे हैं। विदेश विभाग ने कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को विशेष निगरानी सूची में डाला है जहां की सरकारें "धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन" में या तो लिप्त हैं या उसे होने दे रही हैं। पोम्पियो ने कहा, "धार्मिक स्वतंत्रता एक अहस्तांतरणीय अधिकार है और मुक्त समाजों का आधार है जिन पर वे फलते-फूलते हैं। आज अमेरिका ने एक बार फिर उन लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाया है जो यह आजादी चाहते हैं।"

अमेरिका ने अल शबाब, अल कायदा, बोको हराम, हयात तहरीर अल शम, हूथी, आईएसआईएस, आईएसआईएस-ग्रेटर सहारा, आईएसआईएस-वेस्ट अफ्रीका, जमात नासर अल इस्लावल मुस्लिमिन और तालिबान को "विशेष



चिंता का विषय बने संगठन" बताया। पोम्पियो ने कहा कि म्यांमार और उज्बेकिस्तान की सरकारों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान की गई उल्लेखनीय एवं ठोस प्रगति के चलते उन्हें विशेष निगरानी सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, "कानून सबंधी साहसी सुधारों के चलते ये देश अन्य राष्ट्रों के लिए आदर्श हैं।" रक्षा मंत्री ने कहा कि अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है और अमेरिका दुनियाभर में धर्म के नाम पर होने वाले दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न को खत्म करने के

लिए अथक काम करता रहेगा। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग ने विदेश विभाग द्वारा दस राष्ट्रों को विशेष चिंता का विषय बने देशों (कट्टीज ऑफ़ पार्टीक्यूलर कंसर्न या सीपीसी) की सूची में डालने के कदम की सराहना की है। हालांकि विदेश विभाग ने आयोग द्वारा भारत, रूस, सीरिया और वियतनाम को भी सीपीसी सूची में डालने की अनुशंसा स्वीकार नहीं की।

न्यूजीलैंड की मस्जिदों में हमला करने वाले शख्स ने की थी भारत की यात्रा, बिताए थे 3 महीने

मेलबर्न। (एजेंसी)।

गत वर्ष क्राइस्टचर्च की दो मस्जिदों पर हमला कर 51 मुस्लिमों की जान लेने वाले ब्रेंटन टैरेंट ने न्यूजीलैंड जाने से पहले भारत समेत कई देशों की यात्रा की थी। हमले से संबंधित एक विस्तृत रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई जिसमें यह जानकारी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार टैरेंट ने भारत में तीन महीने बिताए थे। पिछले साल 15 मार्च को हुए आतंकी हमले में उन्होंने लोग घायल हुए थे और मारे गए लोगों में पांच भारतीय भी शामिल थे। 'रॉयल कमीशन ऑफ़ इंक्वायरी' की 792 पेज की रिपोर्ट में बताया गया है कि तीस वर्षीय हमलावर ने स्कूल छोड़ने के बाद एक स्थानीय जिम में 2012 तक व्यक्तिगत प्रशिक्षक के तौर पर काम किया था। रिपोर्ट में कहा गया, "उसने वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर उसके बाद कभी काम नहीं किया। इसकी जानकारी उसके पिता के पास पर जीता रहा।



अपने पिता से प्राप्त पैसों से उसने कई देशों की यात्रा की। पहले, 2013 में वह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया गया तथा उसके बाद 2014 से 2017 तक उसने दुनियाभर के देशों की यात्रा की। रिपोर्ट के अनुसार टैरेंट ने 15 अप्रैल 2014 से 17 अगस्त 2017 के बीच अकेले यात्रा की। इस दौरान वह उत्तर कोरिया की यात्रा पर एक समूह के साथ गया था। रिपोर्ट को तैयार करने में लगभग अठारह महीने लगे। इसमें कहा गया, "सबसे लंबे समय तक वह भारत में रहा जहां वह 21 नवंबर 2015 से 18 फरवरी 2016 तक

रहा। वह एक महीने या उससे अधिक समय तक चीन, जापान, रूस, दक्षिण कोरिया इत्यादि देशों में रहा।" जांच रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि टैरेंट ने भारत में तीन महीने के दौरान क्या किया।

'द न्यूजीलैंड हेराल्ड' अखबार की खबर के अनुसार इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं कि विदेश में घूमते हुए टैरेंट किसी चरमपंथी समूह के संपर्क में आया या उसने हमला करने का कोई प्रशिक्षण लिया। जांच रिपोर्ट के अनुसार यह नहीं माना जा सकता कि टैरेंट द्वारा की गई यात्राओं से उसे हमला करने की प्रेरणा मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। इसलिए उसने यात्राएं की। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि टैरेंट इंटरनेट पर कट्टरपंथी सामग्री और ऐसी विचारधारा वाले यूट्यूब चैनल देखा करता था। रिपोर्ट के अनुसार उसने प्रवास और ईसाइयत तथा इस्लाम के बीच ऐतिहासिक लड़ाई का गहन अध्ययन किया था।

डब्ल्यूएचओ ने लोगों को दिया संदेश, 'गले मिलने' और विशेष सावधानी बरतने की दी सलाह

जिनेवा। (एजेंसी)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने संदेश में लोगों से छुट्टियों के दौरान विशेष सावधानी बरतने और 'गले मिलने' से परहेज करने के लिए कहा है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आपात मामलों के प्रमुख डॉ. माइकल रेयान ने सोमवार को कहा कि खासकर अमेरिका में कोविड-19 के मामलों और संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसका यही मतलब है कि लोगों को इस साल अपने प्रियजनों के ज्यादा करीब आने से बचना चाहिए।



डॉ. रेयान ने कहा, "अमेरिका में महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। यह व्यापक रूप में फैल गया है।" उन्होंने कहा, "अमेरिका में बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली और आधुनिक तकनीक हैं, वहां एक मिनट में संक्रमण से

देशों में लोगों के लिए 'करीबी संपर्क' से बचने का परामर्श जारी किया है। कोविड-19 पर डब्ल्यूएचओ की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोवे ने कहा कि संक्रमण के अधिकतर मामले साथ भोजन करने और साथ रहने के कारण हुए हैं। हालांकि यह बात पाना मुश्किल है कि यह वायरस वास्तव में किस तरह से फैला।

रेयान ने कहा, "महामारी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों से एक दूसरे से दूर रहने और गले नहीं मिलने के लिए कहा है।" ब्रिटेन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्रिस व्हिट्टी ने भी नवंबर में ब्रिटिश नागरिकों से कहा था कि अगर वे अपने बुजुर्ग प्रियजनों को जीवित और स्वस्थ देखना चाहते हैं और आगे उन्हें गले लगाना चाहते हैं तो इन छुट्टियों में उनसे गले मिलने और चूमने से परहेज करें।

काठमांडू। (एजेंसी)।

सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) के भीतर गुटबाजी और बाहर राजशाही के समर्थकों से चुनौतियों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को बैठक बुलाई। उन्होंने देश में कोविड-19 महामारी और संविधान विरोधी गतिविधियों से मुकाबले के लिए दलों से एकजुटता का आह्वान किया। ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने बताया कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास बालुवाटार में दिन में ग्यारह बजे बैठक शुरू हुई। बैठक को संबोधित करते हुए ओली ने कोविड-19 महामारी और देश में बढ़ रही असंवैधानिक और हिंसक गतिविधियों के खिलाफ अलग भागों में रैलियां निकाल रहे हैं। ये संगठन देश में राजशाही और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गया है। ओली को पार्टी के भीतर से भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल देहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी खेमे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।



नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गयी है जब राजशाही के समर्थन में कुछ संगठन राजधानी काठमांडू समेत देश के अलग-अलग भागों में रैलियां निकाल रहे हैं। ये संगठन देश में राजशाही और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गया है। ओली को पार्टी के भीतर से भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल देहल 'प्रचंड' के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी खेमे ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बताया "तीसरी दुनिया देश", चुनाव परिणामों को दी कानूनी चुनौती

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में घोखाघड़ी का आरोप लगाते हुए तथा मतों के बड़े पैमाने पर फर्जीबाड़े के निराधार दावों को दोहराते हुए अमेरिका को "तीसरी दुनिया देश" के समान बताया। पहलवान एवं कोच जॉन गबल को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ़ फ्रीडम सम्मान प्रदान करने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव "हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का कारण" बना। उन्होंने कहा, "यह तीसरी दुनिया के देश के समान है- मत एक ऐसी मशीनरी के जरिए हर ओर से आ रहे थे जिसके मालिक का किसी को पता नहीं, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। उनमें गडबड़ियां थीं। वे हजारों मत भेजते पाए गए, सारे के सारे भेजे खिलफ।" राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडन जीत चुके हैं लेकिन ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है तथा चुनाव परिणामों को कानूनी चुनौती दी है। राज्यों के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर घोखाघड़ी की बात से इन्कार किया है। अनेक राज्यों के चुनाव अधिकारियों ने बाइडन को विजेता घोषित कर दिया है। ट्रंप ने कहा, "यह एक तीसरी दुनिया के देश की तरह हुआ। मेरे खयाल से मामला बन गया है। अब हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि अगले कुछ दिन में कुछ बड़ा होने वाला है।" मेडल ऑफ़ फ्रीडम पाने वाले गबल अमेरिकी इतिहास में इस सम्मान से नवाजे गए पहले पहलवान हैं।



वे हजारों मत भेजते पाए गए, सारे के सारे भेजे खिलफ।" राष्ट्रपति चुनाव जो बाइडन जीत चुके हैं लेकिन ट्रंप ने हार स्वीकार नहीं की है तथा चुनाव परिणामों को कानूनी चुनौती दी है। राज्यों के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर घोखाघड़ी की बात से इन्कार किया है। अनेक राज्यों के चुनाव अधिकारियों ने बाइडन को विजेता घोषित कर दिया है। ट्रंप ने कहा, "यह एक तीसरी दुनिया के देश की तरह हुआ। मेरे खयाल से मामला बन गया है। अब हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि अगले कुछ दिन में कुछ बड़ा होने वाला है।" मेडल ऑफ़ फ्रीडम पाने वाले गबल अमेरिकी इतिहास में इस सम्मान से नवाजे गए पहले पहलवान हैं।

सार समाचार

कलराज मिश्र ने कहा, उद्योगों की आवश्यकता के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार हों

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कुशल मानव संसाधन को जरूरी बताते हुए मंगलवार को कहा कि शिक्षाविविध उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें, जो राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास में उपयोगी हो सकें। मिश्र ने मणिपाल विश्वविद्यालय और राजस्थान चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थाओं एवं उद्योगों के समन्वय से शोध एवं अनुसंधान को ऐसे कार्य किए जाने चाहिए, जिनसे राष्ट्रीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग मानव हित में हो सके। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से कहा कि वे ऐसे पाठ्यक्रम बनाएं, जिनसे छात्र स्वरोजगार की तरफ प्रवृत्त होकर रोजगार देने के योग्य भी हो सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल विकसित करने पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए।

पीएम मोदी ने की प्रकाश सिंह बादल से बात, दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल से बात कर उन्हें उनके 93वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। केंद्र सरकार सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों को किसान विरोधी करार देते हुए बादल इसकी कटु आलोचना करते रहे हैं। सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी ने फोन कर बादल को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान मोदी नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। ज्ञात हो कि बादल ने सोमवार को मोदी से तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की अपील की थी। उन्होंने दावा किया था कि इन कानूनों ने देश को गहरे संकट में ला दिया है। लंबे समय तक भाजपा के सहयोगी रहे अकाली दल ने कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से नाता तोड़ लिया था। बादल इन कानूनों के विरोध में पद्म विभूषण सम्मान लौटाने की घोषणा कर चुके हैं।

किसानों के समर्थन में एक दिन के अनशन पर बैठे अन्ना हजारे



पुणे। केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे मंगलवार को एक दिन के अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को 'भारत बंद' रखने की अपील भी की है। हजारे ने कहा कि मोदी ने आंदोलन होना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और वह किसानों के हित में कदम उठाए। हजारे ने एक रिकॉर्डिंग संदेश में कहा, ' मैं देश के लोगों से अपील करता हूँ, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, वह पूरे देश में चलना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है और इसके लिए किसानों को सड़कों पर उतरना होगा। लेकिन कोई हिंसा ना करें।'

हजारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रालेगण सिद्धि गांव में अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सड़कों पर आने और अपना मुद्दा हल कराने का यह 'सही समय' है। उन्होंने कहा, ' मैंने पहले भी इस मुद्दे का समर्थन किया है और आगे भी करता हूँ। हजारे ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसपी) को स्वायत्तता देने और एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने सरकार को सीएसपी को स्वायत्तता नहीं देने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों ना लागू करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, ' सरकार सिर्फ आश्वासन देती है, कभी मांगें पूरी नहीं करती।'

कांग्रेस विधायक ने सबित पात्रा को भेजा कानूनी नोटिस, जहाँ क्या है पूरा मामला

कटक। ओडिशा में कांग्रेस के एक विधायक ने सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता को कानूनी नोटिस भेजा और आपराधिक मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। बाराबाती-कटक सीट से कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने उच्चतम न्यायालय के वकील शाशत सिंह के जरिए भेजे नोटिस में कहा है कि उनकी छवि को कथित रूप से खराब करने के लिए पात्रा तत्काल सार्वजनिक तौर पर उनसे माफी मांगें नहीं तो वह भाजपा नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा कर देंगे। पात्रा ने एक दिसंबर को मीडिया के एक दफे के समक्ष आरोप लगाया था कि कांग्रेस के सभी नौ विधायकों ने नयागढ़ जिले में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या के मामले में घुबे रहने के लिए और बीजद के मंत्री रामलु कुमार साहू का समर्थन करने के लिए सत्तारूढ़ बीजद से पैसा लिया है। साहू ने इस मामले में कथित रूप से आरोपियों को संरक्षण दिया है। पात्रा की ओर से तत्काल टिप्पणी प्राप्त नहीं हो सकी।

आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नजरबंद होने का किया दावा, दिल्ली पुलिस ने किया खारिज

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सिंधू बॉर्डर पर केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। पुलिस ने हालांकि पार्टी के दावों को खारिज किया है। केजरीवाल ने सिंधू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से सोमवार को मुलाकात की थी। आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को नजरबंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया, ' गृह मंत्रालय के निर्देश पर, दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को सिंधू बॉर्डर पर किसानों से मिलने के बाद से ही नजरबंद कर दिया है। किसी को भी उनके आवास जाने या वहां से बाहर आने की

अनुमति नहीं है, उन्हें किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। जब हमारे विधायक मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे, तो उन्हें पीटा गया और सड़कों पर धकेल दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा।'

भारद्वाज ने आरोप लगाया, 'भाजपा नेता दरवाजों पर खड़े हैं और पुलिस कर्मी उनको आने दे रहे हैं। वहां कई अवरोधक लगाए गए हैं और घरेलू सहायिका को भी घर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। केन्द्र को डर है कि इस 'भारत बंद' में अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री ने किसानों का साथ दिया तो उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा।' महापौर, उप महापौर और भाजपा के नेतृत्व वाले शहर के तीनों नगर निगमों के अन्य वरिष्ठ नेता 'बकाया राशि' देने की मांग को लेकर सोमवार से ही केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। भारद्वाज ने कहा कि आप के

सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री को 'रिहा' किया जाए। उन्होंने कहा, 'हमसे कहा गया है कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से सीधे आदेश है कि किसानों का प्रदर्शन जारी रहने तक केजरीवाल को नजरबंद रखा जाए। आज, हमारे पार्टी के सदस्य यहां एकत्रित हुए हैं और हम केजरीवाल के आवास की ओर जाएंगे। अगर पुलिस ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो भी हम उनके आवास तक जाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि केजरीवाल को रिहा किया जाए।' इन सभी दावों को खारिज करते हुए, दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह सच नहीं है। मुख्यमंत्री कहीं भी आया जा सकते हैं। हमने उनके आवास के बाहर अपने सुरक्षा कर्मी तैनात किए हैं। बल्कि वह कल शाम भी बाहर आए थे।'

उन्होंने कहा, 'लोगों की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं है। भाजपा और आप के

सदस्यों के बीच किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए हमने एहतियाती तौर पर अपने दस्ते वहां तैनात किये हैं।' पुलिस उपयुक्त (उत्तर) एंटो अल्फोंस ने भी केजरीवाल के आवास के प्रवेश द्वारा की तस्वीर साझा की और सभी आरोपों को खारिज किया। डीसीपी ने कहा, 'मुख्यमंत्री को नजरबंद करने के आरोप गलत हैं। वह कानून के शासन में स्वतंत्रता से कहीं भी आने-जाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आवास के प्रवेश द्वारा की तस्वीर सब स्पष्ट करती है।' आप के अन्य नेताओं ने भी आरोप लगाया कि केजरीवाल किसानों को समर्थन ना दें पाएँ इसलिए उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया, 'सिंधू बॉर्डर से आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया है। सरकार नहीं चाहती कि केजरीवाल किसानों के साथ खड़े हों और इसलिए ही यह



कदम उठाया गया है।' दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, 'केजरीवाल को नजरबंद कर, केन्द्र किसानों के समर्थन में उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है।' आम आदमी पार्टी ने किसान संगठनों द्वारा आहूत 'भारत बंद' को पूरा समर्थन दिया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर बीते 13 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत बंद के दौरान दिग्विजय सिंह ने साधा मोहन भागवत पर निशाना

इंदौर (मध्यप्रदेश)। (एजेंसी)।

राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को नये कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोलने के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। 'भारत बंद' के दौरान यहां छवनी क्षेत्र स्थित संयोगितागंज अनाज मंडी में कांग्रेसों के विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए सिंह ने कहा, भागवत (संघ समर्थित) भारतीय किसान संघ (बीकेएस) से कहें कि वह नये कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर (आंदोलनरत) किसानों के साथ खड़ा रहे और धरना दे। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे, तो हम मानेंगे कि आप सब नाटक-नाटक केवल वोट के लिए करते हैं और समाज एवं धर्म के नाम पर महज राजनीति करते हैं।

गौरतलब है कि संघ समर्थित बीकेएस ने

सोमवार को कहा था कि वह नये कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को बुलाए गए 'भारत बंद' का समर्थन नहीं करता है, लेकिन इन कानूनों में कुछ सुधार होने चाहिये। सिंह ने सूबे की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान दावा किया, नये कृषि कानूनों के अमल में आने के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े उद्योगपति भारत के कृषि उत्पादों का वह विशाल बाजार हथिया लेंगे, जिसका आकार 12 लाख करोड़ रुपये और 15 लाख करोड़ रुपये के बीच आंका जाता है। उन्होंने कहा, बड़े उद्योगपति मनमाने दाम पर किसानों की उपज खरीदेंगे। इससे देश के कारोबारी उनके कमीशन एजेंट बनने को मजबूर हो जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने यह दावा भी किया कि अमेरिका सरीखे विकसित देशों के हितों की पैरवी करने वाले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दबाव में मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में इस निकाय के साथ गुप्त समझौता

किया था और भारत के नये कृषि कानून इस कथित करार का ही परिणाम है।

उन्होंने आरोप लगाया, नये कृषि कानून गरीबों को सस्ता अनाज मुहैया कराने वाली उचित मूल्य की दुकानें और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से फसलों की खरीदी समाप्त करने के पश्च्यंत्र की शुरुआत है, ताकि बड़े उद्योगपति किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का शोषण कर सकें। सिंह ने कहा, गेहूँ, चना और सोयाबीन सरीखी फसलें एमएसपी से नीचे बिकने के कारण किसानों को घाटा हो रहा है। आखिर हम अन्नदाताओं को लेकर मोदी के वचनों पर भरोसा कैसे करें? उन्होंने मोदी सरकार पर हमले जारी रखते हुए कहा, जैसा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी के संरक्षण में सूट-बूट की सरकार चल रही है, जबकि दूसरी ओर गरीब, किसान, छोटे व्यापारी, मजदूर, हम्माल और तुलावटी हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट ने बनाया रिकॉर्ड, राजनीति में सबसे ज्यादा किया गया रीट्वीट

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोविड-19 महामारी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद के साथ दीप जलाने का अनुरोध करने वाला किया गया ट्वीट, ट्विटर पर जमकर ट्वीट किया गया। यह ट्वीट राजनीति में सबसे अधिक रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट बन गया। ट्विटर ने मंगलवार को यह घोषणा की। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, मोदी ने नागरिकों से नौ मिनट के लिए सभी लाइट बंद करने और 5 अप्रैल को लैंप या टॉर्च या सेलफोन फ्लैश लाइट जलाने का आग्रह किया था।

बिजनेस में, सबसे ज्यादा रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट रतन टाटा का रहा, जिन्होंने कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का सपोर्ट करने की प्रतिबद्धता जताई थी। शीर्ष उद्योगपति ने महामारी से प्रभावित समुदायों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में कंपनी की ओर से 500 करोड़ रुपये की मदद देने की घोषणा की थी।

2020 में ट्विटर पर कंवर्सेशन रहा अद्भुत

ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनोष

माहेश्वरी ने कहा कि जिस तरह का यह साल रहा है, 2020 में ट्विटर पर कंवर्सेशन अद्भुत था। इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई से लेकर, उत्सव के क्षणों में आनन्दित होना, उन समुदायों के लिए खड़े होना जो महामारी से प्रभावित हुए, शो, रुचियों और यादों के संबंध में बॉन्डिंग, भारत इस साल साथ में ट्विटर पर खबूसूरती से आया।

20 फीसद हुई वृद्धि

यह वर्ष माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर फंटाइन वर्कर्स के लिए आधार की भावना भी लाया। डॉक्टर और शिक्षकों के प्रति विशेष सम्मान की भावना के साथ, विश्वभर में कृतज्ञता या आधार व्यक्त करने वाले ट्वीट्स में 20 फीसद की वृद्धि हुई।

इन मुद्दों पर भी हुआ जमकर ट्वीट

कोविड-19 को छोड़कर प्रशंसकों ने सुशांत सिंह राजपूत और उनके करियर को श्रद्धांजलि दी और हाथरस में एक दलित युवती के कथित दुष्कर्म की निंदा की। फरवरी में नेवेली में अपने प्रशंसकों के साथ अभिनेता विजय की सेल्फी सबसे ज्यादा रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट था, जिसका जश्न तमिल सितारों ने ट्विटर पर अपने समुदाय के साथ मनाया।

भाजपा फैला रही है झूठ, रैलियां आयोजित कर लोगों की हत्याएं करवा रही : ममता

रानीगंज (पश्चिम बंगाल)। सिलीगुड़ी में प्रदर्शन मार्च के दौरान भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि 'भगवा पार्टी अपनी रैलियों में लोगों को मार रही है।' भाजपा ने पार्टी कार्यकर्ता उलेन रॉय की हत्या के विरोध में और उत्तर बंगाल में राज्य सचिवालय 'उत्तरकन्या' तक सोमवार के मार्च के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर मंगलवार को 12 घंटे के बंद का आह्वान किया था। बनर्जी ने रानीगंज में जनसभा में आरोप लगाया, 'भाजपा झूठ फैलाने में लिस है। वह लोगों की हत्याएं करवा रही है। वह धरना, रैली कर लोगों की हत्याएं करवा रही है।' बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सरकारी नियंत्रण वाली कोयला खदानों को बेचने की अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा, 'कोयला माफिया भगवा पार्टी के संरक्षण में फल-फूल रहे हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'मैंने पेशकश की थी कि अवैध (कोयला) खदानों को केंद्र और राज्य साथ मिलकर कानूनी मंजूरी दे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।



दिल्ली और काशी के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, राम नगरी भी है रूट में शामिल

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

देश में बुलेट ट्रेन को लेकर मोदी सरकार काफी सक्रिय है। सरकार तेज गति से ट्रेन चलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता लगातार दिखा रही है। देश में पहले बुलेट ट्रेन की तैयारी जेरो-शोर्ट पर है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी जिसके लिए रूट का पर काम फिलहाल जारी है। इस बीच दिल्ली और काशी को जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन योजना पर काम शुरू हो गया है। इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए कई कदम भी उठा लिए गए हैं। इसके लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने रेल मंत्रालय को अपनी डीपीआर भी सौंप दी है। माना जा रहा है कि डीपीआर तैयार करने के लिए ग्रांडड सर्वेक्षण किया जाएगा।

लेकिन इस बुलेट ट्रेन परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इससे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या भी जुड़ सकेगी। दिल्ली-काशी बुलेट ट्रेन परियोजना कोरिडोर के लिए मदद को सामने आया है। खास बात यह है कि बुलेट ट्रेन परियोजना का विस्तार अयोध्या तक हो जाने के बाद पर्यटन और अयोध्या के लिए और भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर और लखनऊ जैसे शहर शामिल हैं। सूत्र बता रहे हैं कि यह ट्रेन दिल्ली से मथुरा, इटावा, कानपुर के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ के बाद यह ट्रेन रायबरेली और प्रयागराज के रास्ते वाराणसी जाएगी। वाराणसी के बाद इसे आगे अयोध्या तक जोड़ा गया है। कुल मिलाकर इस बुलेट ट्रेन कोरिडोर की लंबाई 865 किलोमीटर हो रही है।

यह भी दावा किया जा रहा है कि इस ट्रेक को नोएडा में निर्मित होने वाले जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। कहा जा रहा है कि जवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर ही बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी बनाने की योजना है। जाहिर सी बात है कि इस बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण के बाद से उत्तर प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए बाकायदा सरकारी एजेंसी आगे काम में जुट गई है। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से इस दिल्ली-काशी बुलेट ट्रेन परियोजना कोरिडोर के लिए मदद को सामने आया है। खास बात यह है कि बुलेट ट्रेन परियोजना का विस्तार अयोध्या तक हो जाने के बाद पर्यटन और अयोध्या के लिए और भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

शिवसेना ने नए कृषि कानूनों का कभी समर्थन नहीं किया : संजय राउत

मुंबई। (एजेंसी)।

शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों का कभी समर्थन नहीं किया और भाजपा गलत आरोप लगा रही है। वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राकांपा ने कहा कि बाता के जरिए किसानों की समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार का नैतिक दायित्व है। राउत ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ 'भारत बंद' कर रहे किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बात करनी चाहिए। शिवसेना नेता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि 'गैर राजनीतिक बंद' को देशभर से लोगों का समर्थन मिल रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने

'भारत बंद' को अपना समर्थन दिया है।

राउत ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस की उस टिप्पणी को खारिज किया कि शिवसेना ने लोकसभा में नए कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने ऐसा कभी नहीं किया। राउत ने कहा कि बंद में कोई राजनीति नहीं है और यदि सरकार के पास दिल है तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को किसानों से बात करनी चाहिए। शिवसेना नेता ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राकांपा प्रमुख शरद पवार किसानों के मुद्दे पर अन्य विपक्षी नेताओं के साथ बुधवार को निश्चित ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। वहीं, राकांपा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यदि समाज के किसी तबके में नाराजगी है तो वार्ता के जरिए मुद्दे का समाधान करना सरकार का नैतिक दायित्व है। उन्होंने ट्वीट किया,

'किसान हमारा पेट भरते हैं। यदि समाज के किसी तबके में नाराजगी है तो वार्ता के जरिए मुद्दे का समाधान करना सरकार का नैतिक दायित्व है।' महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री एवं राकांपा नेता राजेश टोपे ने अपने ट्वीट में कहा, 'किसानों को मेरा समर्थन है।'

इस बीच, किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा लाए गए नए कृषि कानून कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। पूर्व सांसद एवं स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के नेता राजू शेठ्टी ने कहा कि केंद्र को बढ़ते दबाव के चलते कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। संगठन के सदस्यों ने आज सुबह केंद्र के समर्थन में बुलढाना जिले में मलकपुर स्टेशन पर अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। बुलढाना, जालना और औरंगाबाद में विभिन्न किसान संगठनों ने कृषि कानूनों के



विरोध में प्रदर्शन किया। वहीं, किसान नेता रघुनाथ पाटिल ने राकांपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की आलोचना की और कहा कि उन्होंने कृषि मुद्दों पर हमेशा दोहरा

रुख अपनाया है। पाटिल ने कहा कि पवार ने कभी भी किसानों के हितों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया है और उन्होंने कॉर्पोरेट हितों की रक्षा करने की भी कोशिश की थी।

१० साल की किशोरी से रेप के बाद हत्या, शव झाड़ियों से बरामद हुआ शव

सुरत शहर के पांडेसरा क्षेत्र से लापता १० वर्षीय किशोरी का हत्या किया हुआ शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। किशोरी के साथ दुष्कर्म की आशंका के चलते उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्या के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर दूसरे की तलाश शुरू की है। सुरत के उधना के विजयनगर में रहनेवाला श्रमिक परिवार मजदूरी कर जीवनयापन करता है। श्रमिक दंपति के एक पुत्र और १० साल की पुत्री है। दंपति मजदूरी करने जाते तब अपनी संतानों

को पांडेसरा के भेदवाड में रहते अपने भाई के घर भेज देते। जहां दोपहर के वक्त किशोरी घर के निकट खेल रही थी। खेलते खेलते किशोरी अचानक लापता हो गई। जिससे लापता किशोरी की परिवार ने आसपास खोजबीन शुरू की। लेकिन रात तक किशोरी का अता पता नहीं मिलने पर परिवार ने पांडेसरा पुलिस थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके आधार पर पांडेसरा पुलिस किशोरी की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने



स्थानीय सोसायटी में लगे सीसीटीवी के मरे खंगाले, जिसमें उसी सोसायटी में रहनेवाले प्रदीप भेसा के साथ किशोरी दिखाई दी। प्रदीप ने किशोरी को पहले एक होटल में चाय-नाश्ता कराया और बाद में उसे लेकर वहां से निकल गया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने प्रदीप की तलाश शुरू कर दी। इस बीच स्थानीय लोगों ने प्रदीप को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। प्रदीप से पूछताछ में पता चला कि उसने अपने दोस्त आनंद के साथ मिलकर किशोरी

की हत्या की और उसका शव झाड़ियों में फेंक दिया। प्रदीप के इस खुलासे के बाद पुलिस काफिला वहां पहुंच गया, जहां किशोरी को शव फेंका गया था। पुलिस ने झाड़ियों से किशोरी को शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही प्रदीप के दोस्त आनंद की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। पुलिस को आशंका है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। पुलिस को आशंका सही है या नहीं, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चलेगा।

“आज मेरा भारत बंद नहीं रहेगा.. आज तो क्या कभी बंद नहीं रहेगा”

सुरत केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज यानी मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। गुजरात में कहीं मिलाजुला तो कहीं बंद पूरी तरह बेअसर रहा। राज्य के ज्यादातर शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की आम दिनों की तरह रहा। गुजरात में कई लोगों ने बंद का समर्थन किया तो कई ने विरोध किया। सुरत के एक युवक भारत बंद का विरोध किया और इसके लिए उसने अपनी टी शर्ट पर खास संदेश भी लगाया। सुरत के पर्वत पाटिया क्षेत्र में

रहने वाले परेश धाकेचा नामक युवक ने भारत बंद के विरोध में अपनी टी शर्ट पर खास संदेश वाला स्टीकर चिपका रखा था। जिसमें लिखा था “आज मेरा भारत बंद नहीं... और

आज तो क्या कभी बंद नहीं रहेगा।” नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले १३ दिनों से सरकार और किसानों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बुधवार को सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर की बातचीत होगी। उससे पहले किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया था। जिसका कांग्रेस समेत २२ राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। भारत बंद पर गुजरात की बात करें तो राज्यभर में इसका मिलाजुला असर रहा। अहमदाबाद समेत राज्य के अधिकांश शहरों में भारत बंद की हवा निकल गई।



किसान दिल्ली में डेर डाले हुए हैं और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं।

दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

सुरत की दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना से सनसनी फैल गई। यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहनेवाले प्राध्यापक के आत्महत्या करने के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। गत २० नवंबर को प्राध्यापक की शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक तेलंगाणा के मूल निवासी ३१ वर्षीय पूर्णचंद्र राव सुरत की दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में बतौर केमेस्ट्री प्राध्यापक सेवारत थे। राव के दो दिनों से लापता होने पर उनकी खोजबीन शुरू की गई। आज सिक्कुरिटी गार्ड को

पूर्णचंद्र राव के घर भेजा गया। गार्ड ने राव के घर का दरवाजा खटखटया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने पर घर का दरवाजा तोड़ भीतर प्रवेश किया तो छत की हुक से पूर्णचंद्र राव का शव लटक रहा था। पुलिस ने मृतक के तेलंगाणा स्थित परिवार को घटना की जानकारी दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्णचंद्र राव तेलंगाणा में २० नवंबर को शादी के बाद सुरत लौटे थे। पूर्णचंद्र राव दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में कोन्स्ट्रक्शन कर्मचारी थे और इस महीने एक साल पूर्ण हो रहा था। फिलहाल पुलिस राव

गुजरात में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने

तीन राजमार्गों को बाधित किया

केन्द्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने गुजरात के ग्रामीण इलाकों में तीन राजमार्गों को बाधित कर दिया। प्रदर्शन की वजह से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प होने की भी खबर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद को विरामगांम से जोड़ने वाले राजमार्ग को साणंद के पास बाधित कर दिया और

सड़क पर जलते हुए टायर रख दिए। प्रदर्शनकारियों के एक अन्य समूह ने वडोदरा में राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित किया। प्रदर्शनकारियों ने भस्व और दाहेज को जोड़ने वाले राजमार्ग को नंदेलाव के पास बाधित कर दिया। अहमदाबाद में उपद्रव कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भारत बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ लगाई है, जिसके तहत चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

गुजरात में भारत बंद कहीं मिलाजुला तो कहीं बेअसर रहा

केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने मंगलवार को बंद का आह्वान किया था। गुजरात सरकार ने बंद निष्फल कर दिया तो विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरी तरह सफल होने का दावा किया। राज्यभर में भारत बंद कहीं मिलाजुला असर दिखा तो कहीं पूरी तरह बेअसर रहा। राज्य के ज्यादातर शहरों में सड़कों पर ट्रैफिक आम दिनों की रहा। बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी रोज की भांति कार्यरत रहे। बंद को देखते हुए गुजरात पुलिस महानिदेशक ने कल रात से ही राज्य में धारा १४४ लगाते हुए पुलिस को एलर्ट कर दिया था। गुजरात कांग्रेस के

कार्यकर्ता कल रात से ही बंद को सफल बनाने के प्रयासों में जुट गए थे। राजकोट में देर रात टायर जलाकर कृषि कानूनों का विरोध करने के आरोप में पुलिस ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को वडोदरा नेशनल हाईवे, अहमदाबाद-मालिया हाईवे पर साणंद के निकट और भस्व-दहेज रोड पर टायर जलाकर चक्काजाम किया गया। उत्तरी गुजरात के थराद रोड पर टायर जलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। अरवल्ली के शामलाजी-भिलोडा-ईंडर रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोडवेज की बसों की हवा निकालकर

चक्काजाम किया। गुजरात-राजस्थान सीमा बंद कराने जा रहे कांग्रेस विधायक कांति खराडी को पुलिस ने अमीरागढ के निकट हिरासत में ले लिया। सौराष्ट्र में भी भारत बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं जबरन दुकानें बंद करवाई गई तो कहीं चक्काजाम किया गया। जामनगर की नगर पार्श्व जैनब खफी कृषि कानूनों के विरोध में बैलगाड़ी पर सवार होकर निकली। पुलिस ने नगर पार्श्व को बैलगाड़ी से उतारकर हिरासत में ले लिया। जामनगर में बंद के समर्थन में बाइक रैली भी निकाली गई। साथ ही जामनगर



में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला फूंकने का निष्फल प्रयास

भी किया गया। अमरेली में भारत बंद को सफल बनाने के लिए

विपक्ष के नेता परेश धानाणी व्यापारियों से बंद को समर्थन

करने की अपील करने एक्टिवा पर निकले। उस वक्त पुलिस और परेश धानाणी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि परेश धानाणी पुलिस को चक्का देकर वहां से निकल गए। जिसके बाद धानाणी और पुलिस के बीच कुछ समय तक पकड़ा पकड़ी का खेल चला। आखिरकार पुलिस ने परेश धानाणी को भी हिरासत में ले लिया। राजकोट में पुलिस ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस की महिला प्रमुख और शहर कांग्रेस की महिला प्रमुख समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। दक्षिण गुजरात के सुरत शहर के उधना और वराछा में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन

किया। जिसमें महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई। पुलिस ने कांग्रेस की नगर पार्श्व और महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी क्षेत्र में भारत बंद का समर्थन करने पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बीआरटीएस की ३ बसें रोक उसकी चाबी निकाल ली। बस बंद होने से उसमें सवार यात्रियों को ड्राइवर सीट की ओर से बस से बाहर निकलना पड़ा। अहमदाबाद में भारत बंद का कहीं असर नहीं दिखा। बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान आम दिनों की तरह खुले रहे और सड़कों पर ट्रैफिक भी पूर्ववत रहा।

किसानों के नाम पर राजनीति की रोटियां सेंक रही है कांग्रेस - मुख्यमंत्री

मेहसाणा (क्रांति समय) 7 मुख्यमंत्री विजय स्वामी ने किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह कर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने निकले कांग्रेसियों से तीखा सवाल किया कि भूतकाल में कांग्रेस के शासन में किसान १८ फीसदी व्याज पर पैसा लेता था और समर्थन मूल्य पर एक सपए की भी खरीदी नहीं होती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट को निरस्त कर किसानों को देशभर में कहीं भी फल, सब्जी सहित अन्य फसलों को बेचने की छूट देने का वचन दिया था। अब जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह साहसिक कदम उठाया है तब किस मुंह से विरोध करने निकले हैं। विजय स्वामी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को धनिया और मैथी फर्क नहीं पता,

मेहसाणा जिले के लिए २८७ करोड़ की जलापूर्ति योजना का स्वाणी ने किया भूमिपूजन



इसके बावजूद कृषि कानूनों पर जान बांट रहे हैं? मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में १५ हजार करोड़ सपए के खेत उत्पादों की खरीदी की है। यही नहीं, किसान को दिन के दौरान बिजली मुहैया कराने के लिए किसान सूखोदय

योजना और पर्याप्त सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया है। उन्होंने गुजरात को एनर्जी सरप्लस राज्य की तरह ही वाटर सरप्लस बनाने के लिए पानी, सिंचाई, कल्पसर और नर्मदा योजना जैसी अनेक योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की

प्रतिबद्धता भी जताई। मंगलवार को उत्तर गुजरात के आर्थिक और व्यापारिक केन्द्र मेहसाणा में २८७ करोड़ सपए की जलापूर्ति योजनाओं का भूमिपूजन करते हुए मुख्यमंत्री विजय स्वामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नागरिकों की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं शुरू कर उन्हें पूर्ण भी कर दिया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भूतकाल में कांग्रेस के शासन के दौरान लोग और उनकी समस्याएं धुला दी गईं जबकि हमने लोगों की समस्याओं और उनके मसलों का समाधान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी संस्कृति विकसित की है जिसमें जिस योजना का भूमिपूजन होता है, उसका लोकार्पण भी भाजपा की सरकार के समय में ही हो

जाता है। अतीत में हालात ऐसे थे कि शिलान्यास का पत्थर रखने के बाद १२-१५ वर्षों तक कोई कार्यवाही नहीं होती थी और योजना के लिए आवंटित बजट चार गुना तक बढ़ जाता था। विशेषकर उत्तर गुजरात के इलाकों में भूतकाल में जलापूर्ति की स्थिति की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि फ्लोराइड और क्षार युक्त तथा बोरेल का पानी पीने से लोग हाथी पैर, हड्डियों के कमजोर और खोखला होने तथा दांत पीले पड़ जाने जैसी बीमारी का शिकार बन जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दशक पूर्व यानी वर्ष २००० से पहले कांग्रेस के शासनकाल में राज्य में केवल ४७०० गांवों में जलापूर्ति योजनाएं थी। २८ फीसदी लोगों को नल से जल मिलता था और दो घड़ा पानी लेने के लिए बहनों को कई

किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी। स्थिति ऐसी थी कि समूह जलापूर्ति योजनाओं की पाइपलाइन टूटी-फुटी अवस्था में रहती थी और दूरदराज के गांवों में तो पानी ही नसीब नहीं होता था। स्वाणी ने १९८० से ९० के दशक में राज्य में पानी की विकराल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में ट्रेन के जरिए और राज्य के बाकी के हिस्सों में टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाता था, टैंकर राज के उस दौर में भ्रष्टाचार चरम पर था। पानी के अभाव में लोगों को पलायन करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि पानी की ऐसी विकट स्थिति की जड़ में कांग्रेसियों की भ्रष्टाचारी नीतियां और बेदंगा आयोजन जिम्मेदार हैं। उनके समय में केवल ८ हजार करोड़ सपए का वार्षिक बजट था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार

दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

सुरत की दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना से सनसनी फैल गई। यूनिवर्सिटी के क्वार्टर में रहनेवाले प्राध्यापक के आत्महत्या करने के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। गत २० नवंबर को प्राध्यापक की शादी हुई थी। जानकारी के मुताबिक तेलंगाणा के मूल निवासी ३१ वर्षीय पूर्णचंद्र राव सुरत की दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में बतौर केमेस्ट्री प्राध्यापक सेवारत थे। राव के दो दिनों से लापता होने पर उनकी खोजबीन शुरू की गई। आज सिक्कुरिटी गार्ड को पूर्णचंद्र राव के घर भेजा गया। गार्ड ने राव

के घर का दरवाजा खटखटया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने पर घर का दरवाजा तोड़ भीतर प्रवेश किया तो छत की हुक से पूर्णचंद्र राव का शव लटक रहा था। पुलिस ने मृतक के तेलंगाणा स्थित परिवार को घटना की जानकारी दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूर्णचंद्र राव तेलंगाणा में २० नवंबर को शादी के बाद सुरत लौटे थे। पूर्णचंद्र राव दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में कोन्स्ट्रक्शन कर्मचारी थे और इस महीने एक साल पूर्ण हो रहा था। फिलहाल पुलिस राव के आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।